RNI NO. 45823/86 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2022-23-24, DL(ND)-11/6042/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22 www.indiatodayhindi.in

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 60 (आवरण सहित) वर्ष 36; अंक: 50

मोरबी हादसा
दोषियों को दें सजा

आवारा कुत्ते
मुसीबत से कैसे निबटें

रॉबिन दास
बोलता है गुरु ज्ञानी

16 नवंबर, 2022 50 रुपए

इंडिया टुडे

पादरी मनोहर सिंह,
नारायणगढ़, अमृतसर

पंजाब के पादरी

करिश्माई उपदेशकों की नई जमात बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रही है जिससे मुख्यधारा के सिख समुदाय में खलबली

VISIT…

प्रधान संपादक की कलम से

पंजाब अपने व्यंजनों, संगीत, नृत्य, जोशोखरोश वाले लोगों, हरित क्रांति, और सबसे बढ़कर सिख धर्म का केंद्र होने के लिए मशहूर है. हालांकि, इधर एक और परिघटना धार्मिक हलकों में हलचल पैदा कर रही है. वह है पेंटेकोस्टलवाद का उदय. यह करिश्माई आंदोलन दुनिया भर में ईसाई धर्म की सबसे तेजी से बढ़ती शाखा है और इन दिनों पंजाब के कस्बों और गांवों में ऐसे सैलाब की तरह फैल रहा है कि हर कोई बैठा बस देख रहा है.

इस सैलाब की वजह कुछ मुट्ठी भर पादरी हैं. 'एपोस्टल' या प्रचारक अंकुर योसेफ नरूला उनमें सबसे चर्चित हैं. हिंदू खत्री परिवार में जन्मे, जालंधर में फ्लोर टाइल और मार्बल के कारोबार से जुड़े नरूला 2008 में ईसाई धर्म में दीक्षित हुए और अपनी मिनिस्ट्री सिर्फ तीन लोगों के साथ शुरू की. उनके चर्च ऑफ साइन्स ऐंड वंडर्स का दावा है कि आज दुनिया भर में उसके 3,00,000 अनुयायी हैं. जालंधर के खंब्रा गांव में 65 एकड़ में फैले मुख्य चर्च के अलावा 'अंकुर नरूला मिनिस्ट्री' की शाखाएं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी के साथ एक ग्रेटर लंदन के हैरो में और दूसरी बर्मिंघम में है, जिसका अक्तूबर में ही उद्घाटन हुआ है. उनके जैसे करीब दर्जन भर और हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिसवाले, अफसरशाह, कारोबारी और जमींदर समाज के हर तबके से आते हैं और उपदेश के लिए या तो अपना पेशा छोड़ चुके हैं या हर रविवार को वह भूमिका भी निभाते हैं. सबके पास ढेर सारे अनुयायी, पंजाब में कई सेंटर, यूट्यूब पर ढेरों फॉलोअर हैं और सबसे बढ़कर, सभी चमत्कारी शक्तियों और आस्था उपचार की चमत्कारी उपलब्धियों का दावा करते हैं. वे भूत उतारने से लेकर कैंसर, जोड़ों में दर्द और बांझपन का इलाज करने, नशे से निजात दिलाने, शादी कराने और वीजा दिलाने में मददगार होने जैसे हर मर्ज के इलाज दावा करते हैं.

10 फरवरी, 1999

इस जमात के दूसरे छोर पर हैं गांवों के पादरी. इनकी पांत में आपको पुलिस के एएसआइ, छोटे-मोटे कपड़ा व्यापारी, छोटे-मोटे दर्जी, खेत मजदूर अक्सर अपने घरों के एक हिस्से में संडे सरमन (प्रवचन) आयोजित करते मिलते हैं. वे अनुयायियों के साथ अधिक परिचित तौर-तरीकों से पेश आते हैं. वे अपने ईसाई प्रचार में खुलकर पंजाबी संस्कृति के प्रतीकों—पगड़ी, लंगर, टप्पा, गिद्दा का प्रयोग करते हैं. मैनेजिंग एडिटर सुनील मेनन, डिप्टी एडिटर अनिलेश एस. महाजन और ग्रुप फोटो एडिटर बंदीप सिंह ने पाया कि उनके सत्संग पंजाब के किसी भी प्रचलित धर्म—सिख, हिंदू या सूफी संप्रदाय के धार्मिक आयोजनों जैसे ही एहसास दिलाते हैं. उनके ज्यादातर अनुयायी सबसे शोषित-पीड़ित दलित/आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो पंजाब की फलती-फूलती समृद्धि और उसके एलीट नियंत्रण वाली संस्थाओं से अलग-थलग हैं. ये तबके ही छोटे-बड़े डेरों की ओर जाते हैं, जो उन्हें मुख्यधारा की सामाजिक रूढ़ियों से अलग कुछ जगह मुहैया कराते हैं. लेकिन घोटालों और विवादों की वजह से कुछ डेरों की चमक फीकी पड़ी तो पंजाब की वंचित-पीड़ित जातियों को करिश्माई ईसाइयत में सदियों की जलालत और शोषण से मुक्ति की नई राह दिखी है.

उनकी भारी संख्या से मुख्यधारा की संस्थाओं से बेचैनी बढ़ रही है. ठोस आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एक आकलन के मुताबिक, पादरियों की संख्या 65,000 जितनी भारी है, जो पंजाब के सभी 23 जिलों में फैले हैं, मगर वे सबसे बड़ी संख्या में माझा और दोआब के इलाके और मालवा में फिरोजपुर और फाजिल्का के सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं. जहां तक अनुयायियों की बात है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक, राज्य की कुल आबादी में ईसाइयों की संख्या सिर्फ 1.26 फीसद यानी 3,48,230 है. अब इसे नरूला के 3,00,000 अनुयायियों के दावे से मिलाकर देखिए, जो ज्यादातर पंजाब में ही हैं, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों धर्मांतरण के खिलाफ पुराना हौवा फिर स्वर उठा रहा है. सिख धर्म अपने मूल मूल्यों में उदार और समता पर जोर देता है, लेकिन पिछली सदी में ताकतवर जट सिख समुदाय के वर्चस्व की वजह से सौहार्द्र और प्रतिशोध के द्वंद्व में फंस गया है. हिंदू दक्षिणपंथी धारा के लिए धर्मांतरण का मुद्दा उसके अफसाने में सही ठहरता है. यहां तक कि कैथोलिक चर्च भी पेंटेकोस्टल आंदोलन की ओर लोगों के भारी झुकाव से चकित है.

पंजाब में ईसाई धर्म कोई अजनबी नहीं है. यूरोपीय मिशनरियां यहां 19वीं सदी के मध्य में उतर आई थीं और 1849 में अंग्रेज-सिख युद्ध के खत्म होने के पहले ही धर्मांतरण का आगाज कर चुकी थीं. उसके बाद से कैथोलिक चर्च के साथ-साथ प्रेस्बाइटेरियन, मेथडिस्ट और एंग्लिकन जैसे प्रोटेस्टैंट मुख्यधारा के समुदायों की मौजूदगी यहां रही है. लेकिन असली उछाल 1873 के बाद तकरीबन अगली आधी सदी में आया, जब पंजाब की सबसे उपेक्षित-कलंकित जाति समूहों ने खुद को बपतिस्मा के जरिए मुक्त करना चाहा. तब संख्या पांच लाख तक बढ़ गई थी. बंटवारे के बाद भारत के हिस्से में उसके आधे से कम लोग रह गए. हालात पिछले दशक में दूसरी लहर आने तक स्थिर रहे, जब पादरियों और उनके अनुयायियों की संख्या में इजाफा देखा गया. जाति अभी भी मुख्य वजह है. इसी वजह से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा माझा में सिख परिवारों के ''धर्मांतरण'' को रोकने के लिए नियुक्त किए गए एक्टिविस्ट मंजीत सिंह भोमा कबूल करते हैं, ''अगर ये ईसाई समूह अपने बच्चों को शिक्षा, किताबें या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं तो एसजीपीसी को सोचने की जरूरत है कि उसमें बुरा क्या है.''

पंजाब ऐसे धर्मांतरण विरोधी कानूनों से दूर रहा है, जो कुछ राज्यों में पारित किए गए हैं. फिर भी बड़े पैमाने पर ईसाइयत में धर्मांतरण से सभी तरफ नाराजगी है. आनंदपुर साहिब में 5 सितंबर को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि सिख समुदाय को धर्मांतरण पर अपने रुख पर नए सिरे से विचार करना चाहिए. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 'जवाबी' पहल के तौर पर घर-घर अंदर धर्मसाल जैसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत वॉलंटियर सिख धर्म का प्रचार करने के लिए दरवाजे-दरवाजे जाते हैं.

हालात गरम हो चुके हैं और कट्टर सिख गुट इवेंजेलिस्टों को धमकाने लगे हैं. 29 अगस्त को निहंगों की एक टोली ने अमृतसर के ददौना गांव में एक पेंटेकॉस्टल आयोजन में 'जबरन धर्मांतरण' का आरोप लगाकर हंगामा किया. दो दिन बाद तरन तारन जिले के गांव ठक्करपुरा में नकाबपोश घुसपैठियों ने कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़ की और पादरी की कार जला दी. ईसाई एक्टिविस्टों ने 18 अक्तूबर को विरोध प्रदर्शन किया. पंजाब देश के खूनी बंटवारे का सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है और उसने उग्रवाद का अंधेरा दौर देखा है. दोनों ही धर्म के नाम पर हुए. भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उपासना की आजादी संविधान में निहित है. शायद सबसे अच्छा तरीका सामाजिक-आर्थिक हालात सुधारना ही है, जिससे मजबूर होकर लोग अपनी आस्था बदलते हैं. मुनासिब यही है कि हर कोई सावधानी और नरमदिली दिखाए.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादकः अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सनः कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः मनोज शर्मा
एडिटरः सौरभ द्विवेदी
डिप्टी एडिटरः मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
सीनियर असिस्टेंट एडिटरः पवन वर्मा
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित
वरिष्ठ विशेष संवाददाताः हिमांशु शेखर
विशेष संवाददाताः विनय सुल्तान
राज्य ब्यूरोः पुष्यमित्र (पटना), आनंद चौधरी (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टरः असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर (इंपैक्ट):
विद्या मेनन,
सुपर्णा कुमार
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः सैयद नदीम (चेन्नै)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजरः पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्षः 36; अंकः 50; 10-16 नवंबर, 2022; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
- ग्राहकी चंदा भेजेंः इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- ग्राहक सेवाः कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोनः दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्सः (0120) 4078080. ई-मेलः wecare@intoday.com
- सर्कुलेशन कार्यालयः लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- इंपैक्ट कार्यालयः 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-66063355 फैक्सः 022-66063226
- क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालयः एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**

संपादकः राज चेंगप्पा

सुर्खियां

टाटा-एयरबस प्रोजेक्टः अपने दम पर अपने पंख
पेज 5

छत्तीसगढ़ः नए सिपहसालार
पेज 8

भीतर

फुरसत

रॉबिन दासः जब बोलता है गुरु ज्ञानी
पेज 54

सवाल+जवाब/प्रकाश राजः महामारी से पहले एक फिल्म माफिया था
पेज 58

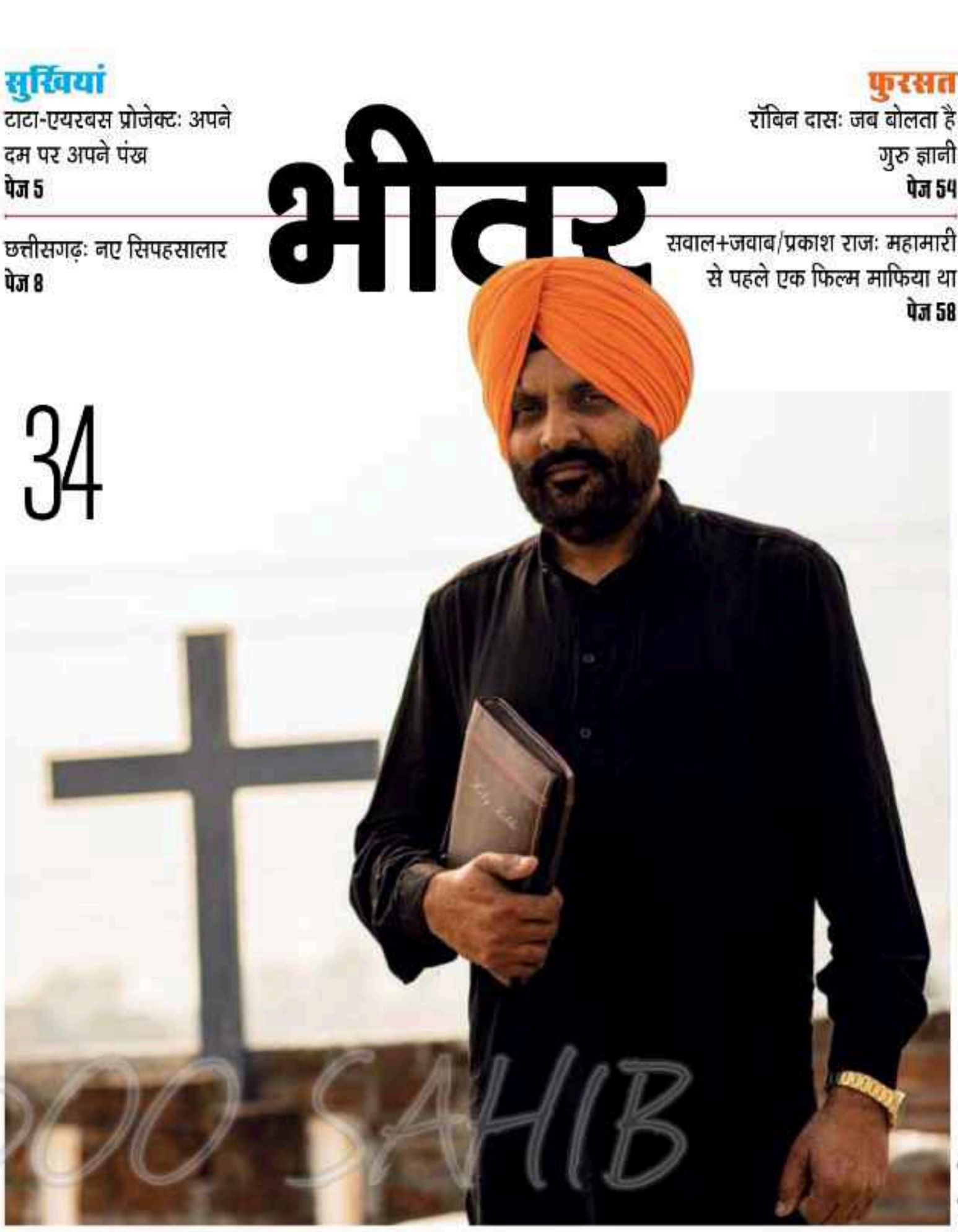

बंदीप सिंह

आवरण कथा

ये पादरी पंजाब के

ईसाई उपदेशकों को अपने धार्मिक असर के विस्तार और ईसाइयत के फैलाव के लिए पंजाब की सबसे शोषित-उपेक्षित जातियों में मिल गई माकूल और उर्वर जमीन.

हिमाचल प्रदेश

20 पहाड़ की 'पथरीली' राह

क्या हिमाचल के मतदाता सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ते हुए भाजपा को दूसरा कार्यकाल देंगे?

संघवाद

22 राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री

कुछ राज्य सरकारों से टकराव ने राज्यपालों की भूमिका की बहस को फिर ताजा कर दिया.

खास रपट

28 मोरबी के कसूरवार

गुजरात के मोरबी हादसे के दोषी आखिर कौन हैं और क्या उन्हें वाकई सजा मिल पाएगी?

आवारा कुत्ते

50 जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई

यह बहस फिर शुरू हो गई कि इनसान और कुत्ते क्या एक साथ प्रेम से रह सकते हैं?

आवरण फोटो : **बंदीप सिंह**

पाठकों के लिए सूचनाः कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आते होंगे. ये विज्ञापन हैं और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

छत्तीसगढ़:
नए सिपहसालार
पेज 8

जम्मू-कश्मीर: फीका
पड़ता उम्मीद का फल
पेज 10

सुर्खियां

झारखंड / हेमंत सोरेन:
आर या पार की तकरार
पेज 14

समाचार सार:
बड़ी बहन
पेज 16

नई उड़ान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और एयरबस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर क्रिश्चियन शेरर वडोदरा में सी-295 प्लांट की आधारशिला रखे जाने के मौके पर

टाटा-एयरबस प्रोजेक्ट

अपने दम पर अपने पंख

प्रदीप आर. सागर

भारत ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस ऐंड स्पेस, एसए कंपनी के साथ भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम वजन के 56 सी-295 परिवहन विमान खरीदने और बनाने के सौदे पर दस्तखत किए थे. तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कारखाना भारत में कहां लगाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अक्तूबर को चुनाव की देहरी पर खड़े गुजरात के वडोदरा में निर्माण इकाई की आधारशिला रखने के साथ इन अटकलों पर विराम लग गया. रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने कहा कि करार के मुताबिक 16 विमान बने-बनाए आएंगे और 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण एयरबस और भारतीय विमान कॉन्ट्रैक्टर यानी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) की अगुआई में टीएएसएल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा. परियोजना कुल 21,935 करोड़ रुपए की है. अहम बात यह कि पहली बार भारत में निजी कंपनी सैन्य विमान बनाएगी.

दरअसल, टाटा-एयरबस संयुक्त उद्यम में यह जो 'निजी' है, इसे ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है. प्रधानमंत्री की तरह कई और लोगों को भी उम्मीद है कि इससे भारत में विमान निर्माण का क्षेत्र एक नई उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा. फिलहाल देश में बेंगलूरू स्थित सरकार के मालिकाना हक वाली एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का संपूर्ण दबदबा है. सवारी और मालवाहक विमानों की

बढ़ती मांग की तरफ इशारा करते हुए मोदी ने वडोदरा में कहा कि भारत को अगले 15 साल में 2,000 से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी.

एलाइड मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में सैन्य परिवहन विमानों का बाजार 2030 तक 45 अरब डॉलर पर पहुंचना तय है. टाटा-एयरबस कारखाने को आइएएफ की तरफ से ऑर्डर किए गए विमान 2031 तक बनाकर देने हैं और उसके बाद वह विमान निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है.

अब जब सरकार ने विमान निर्माण के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं, नीति निर्माता अपनी सारी जरूरतों के लिए शायद एचएएल का मुंह नहीं ताकेंगे, उनके पास दूसरे विकल्प भी होंगे. जिस तरह परिवहन विमानों के लिए टाटा को चुना गया है, लड़ाकू विमान बनाने के लिए दूसरी फर्म को चुना जा सकता है. इसी तरह हेलिकॉप्टर और यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) बनाने का काम अलग-अलग कंपनियों को सौंपा जा सकता है.

आइएएफ के लिए रूसी मूल के सुखोई (लाइसेंस के तहत निर्मित) से लेकर देश में ही डिजाइन और विकसित एलसीए तेजस तक सभी लड़ाकू विमान एचएएल ही बनाती रही है. लड़ाकू विमानों के अलावा एचएएल सशस्त्र बलों के लिए कई प्रकार के हेलिकॉप्टर भी बनाती है. उसके पास अपनी क्षमता से ज्यादा काम है. आने वाले सालों में उसे करीब 1,000 हेलिकॉप्टर बनाकर देने हैं. हाल में एचएएल को एचटीटी-40 प्रशिक्षण विमान बनाने का ऑर्डर दिया गया है. इसके अलावा, आइएएफ 300 से ज्यादा 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस खरीदने वाली है. आइएएफ को 40 एलसीए एमके1 डिलिवर किए जा रहे हैं, तो वहीं उसने इसके अपग्रेड किए गए संस्करण 83 एके1ए विमानों का ऑर्डर दिया है. मध्यम वजन का लड़ाकू विमान एलसीए एमके2 संभवत: 2023 के आखिर या 2024 की शुरुआत में पहली उड़ान भरेगा. ये सब एचएएल मैन्यूफैक्चर कर रहा है.

सैन्य जानकारों का मानना है कि काम के इतने बोझ के कारण ही एचएएल को विमानों की डिलिवरी देने में देरी होती है. उन्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है जब एचएएल अपने काम का बोझ दूसरों के साथ बांटे. एक प्रमुख रक्षा अधिकारी कहते हैं, ''अकेली विमान निर्माता होने की वजह से एचएएल के पास बहुत ज्यादा काम है. इसी वजह से डिलिवरी में बार-बार देरी हुई. एलसीए से लेकर हेलिकॉप्टर तक समय पर डिलिवरी का एचएएल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. उसे निजी कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर काम बांटना चाहिए.'' आइएएफ के कुछ अधिकारियों ने तो समय सीमा चूकने के लिए एचएएल की खुलकर आलोचना तक की. हालांकि मानना होगा कि ठेके देने में अफसरशाही (रक्षा मंत्रालय) की लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं ने एचएएल के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं.

एचएएल के पास के पास काम की भरमार है, विशेषज्ञों के मुताबिक अब समय आ गया है कि वह अपने काम का बोझ दूसरों के साथ बांटे

एचएएल ने 1942 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान कर्टिस पी-36 हॉक और बमवर्षक विमान वुल्टी ए-31 वैंजेंस के लाइसेंसशुदा उत्पादन के साथ विमान बनाना शुरू किया. इतने सालों के दौरान इसने डी हैविलैंड वैम्पायर्स, एमआइजी या मिग-21 के भिन्न रूप, फोलैंड जीनेट्स, मिग-27 के एम वैरिएंट, एसईपीईसीएटी जगुआर, बीएई हॉक और एसयू-30एमकेआइ लड़ाकू विमानों का (लाइसेंस के तहत) उत्पादन किया है.

देश की निजी कंपनियों ने कई बार सरकार से आग्रह किया कि वह उनकी क्षमताओं में भरोसा दिखाए ताकि वे भी सैन्य हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में योगदान दे सकें. सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के डायरेक्टर जनरल एयर वाइस मार्शल अनिल चोपड़ा (सेवानिवृत्त) टाटा-एयरबस सौदे को पहला बहुत अहम बदलाव मानते हैं. वे कहते हैं, ''एक तो परिवहन विमान भारत में बनेंगे और दूसरा निजी क्षेत्र को बेहद शुरुआती ताकत

सी-295

आसमान में मालवाहक

आइएएफ के लिए सी-295 परिवहन विमान बनाने के लिए टाटा-एयरबस संयुक्त उद्यम किसी भी भारतीय निजी कंपनी के लिए पहला उद्यम है और भविष्य की गतिविधियों का संकेत देता है. **21,935 करोड़ रुपए** की इस परियोजना की कुछ खासियतें:

- सी-295 एमडब्ल्यू 5-10 टन क्षमता का परिवहन विमान है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 480 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह आइएएफ के बुढ़ाते एवरो विमानों की जगह लेगा. तेजी से प्रतिक्रिया और पैराशूट से सैनिक तथा सामान उतारने के लिए इसके पिछले हिस्से में ढलान के साथ दरवाजा है. सेमी प्रिपेयर्ड रनवे (कामचलाऊ रनवे) से तेजी से टेक-ऑफ और लैंडिंग इसकी एक और खासियत है. विमान से आइएएफ की ढुलाई की क्षमता मजबूत होंगी
- पहले छह बने-बनाए विमान सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच आने हैं. पहला मेक इन इंडिया विमान सितंबर 2026 में मिलने की उम्मीद है
- रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एयरबस स्पेन के अपने कारखाने में प्रति विमान कुल जितने मानव घंटे काम करती है, उसका 96 फीसद भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के हाथों किया जाएगा. औजारों, सांचों

और टेस्टर के अलावा 13,400 से ज्यादा अनिवार्य कलपुर्जों का निर्माण, 4,600 सब-एसेंबली और सातों बड़ी कंपोनेंट एसेंबली भारत में की जाएंगी. इंजन, लैंडिंग गियर, एविओनिक्स, ईडब्ल्यू सूट सरीखी कई प्रणालियां एयरबस डिफेंस ऐंड स्पेस मुहैया करेगा और विमान में

जोड़ेगा. टीएएसएल एकीकृत प्रणाली के तौर पर विमान का परीक्षण करेगा. विमान की उड़ान के परीक्षण के बाद उसे कारखाने के डिलिवरी केंद्र के जरिए डिलिवर किया जाएगा

- सभी 56 विमानों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां फिट होंगी

- आइएएफ को 56 विमानों की डिलिवरी पूरी करने के बाद मेसर्स एयरबस डिफेंस ऐंड स्पेस को भारत में निर्मित विमान सिविल ऑपरेटरों और सरकार की तरफ से स्वीकृत देशों को निर्यात करने की इजाजत होगी

ब्लूमबर्ग

मिलेगी. इससे एचएएल का एकाधिकार टूटेगा और प्रतिस्पर्धा पैदा होगी.''

विमानन विशेषज्ञ रक्षा निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की बढ़ती मजबूत भूमिका देखते हैं. मसलन, टाटा एयरोस्पेस ऐंड डिफेंस (टाटा एऐंडडी) एएच-64 अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टर के मुख्य ढांचे के अलावा बोइंग कंपनी के सीएच-47 चिनूक हेलिकॉप्टरों का हवाई ढांचा बनाती है. चोपड़ा बताते हैं कि सैन्य परिवहन विमान सी-130जे के हवाई ढांचे के हिस्से भारत में बनाकर दुनिया भर के ग्राहकों को डिलिवर किए जाते हैं. लॉकहीड मार्टिन की कंपनी सिकोर्सकी भी एस-92 हेलिकॉप्टर के केबिन की वैश्विक आपूर्ति के लिए निर्माण आधार के तौर पर हैदराबाद स्थित टीएएसएल पर भरोसा करती है. टाटा ग्रुप सीएफएम इंटरनेशनल एलईएपी इंजन के कलपुर्जे भारत में बनाने के लिए जीई एविएशन के साथ मिलकर काम कर रहा है. गौरतलब यह भी है कि एफ-16 लड़ाकू विमान के पंख भारत में बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने टीएएसएल को चुना है. चोपड़ा कहते हैं, ''हमारा निजी क्षेत्र दुनिया के लिए विमानों के अहम कलपुर्जे बना रहा है, तो उसे विमान क्यों नहीं बनाने चाहिए? निजी क्षेत्र में भरोसा जताने का वक्त आ गया है.''

एलसीए तेजस की डिलिवरी में हुई देरी सबके जेहन में ताजा है. लिहाजा आने वाले वक्त का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान—एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए)—बनाने के लिए निजी भागीदारों के साथ विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के मॉडल पर काम चल रहा है. एसपीवी परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए कानूनी संस्था या कंपनी होती है. रक्षा मंत्रालय ने एएमसीए के लिए क्रियान्वयन मॉडल तैयार करने की खातिर 2019 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व चेयरमैन और नीति आयोग के मौजूदा सदस्य वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में समिति बनाई. महसूस किया गया कि और ज्यादा

भारत का निजी क्षेत्र दुनियाभर की एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए सामान बनाता रहा है, ऐसे में अब उसे और आगे बढ़ने की जरूरत है

कंपनियों को जोड़कर विमान उत्पादन की मौजूदा रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है. समिति की रिपोर्ट ने एएमसीए के लिए एसपीवी बनाने की सिफारिश की. अभी तक डीआरडीओ के तहत काम करने वाली एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) विमान का डिजाइन तैयार करती है और एचएएल उसे बनाती है. मगर एएमसीए के लिए एसपीवी के साथ निजी उद्योग की भूमिका शुरू हो सकती है. मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद एडीए एसपीवी का गठन करेगा. कामों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पर निजी खिलाड़ियों को मैन्यूफैक्चरिंग में ज्यादा बड़ा हिस्सा दिया जा सकता है. दरअसल, एडीए ने एएमसीए से जुड़े कामों के बंटवारे को लेकर तीन सबसे अव्वल निजी कंपनियों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है.

इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पूर्व डिप्टी चीफ एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) एम. माथेश्वरन कहते हैं कि इतने सालों के दौरान सरकार की नीतियों ने एचएएल को भारत में विमानों का अकेला निर्माता बना दिया. वे कहते हैं कि टाटा-एयरबस जेवी को सिविल और सैन्य दोनों विमानों के निर्यात की संभावनाएं तलाशने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सैन्य बल उन्हें बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं दे सकते. माथेश्वरन कहते हैं, ''टाटा को टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और उसे विकसित करके उसका मूल्य संवर्धन करना होगा. ज्यादातर विदेशी कंपनियां अपने भागीदार को ऐसा नहीं करने देतीं. एयरबस की नजर भारतीय बाजार में अपनी बिक्री बढ़ाने पर होगी, भारतीय उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में ले जाने पर नहीं. टाटा को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी एयरबस के बाजार में घुसने की जरूरत है.''

सी-295 के साथ नजीर कायम हो गई है. उम्मीद है कि सरकार और ज्यादा निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में आने देगी, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगी और इस तरह विमान निर्माण में ज्यादा दक्षता और कड़ी मेहनत का विकल्प चुनेगी. भारतीय वायु सेना इसके लिए एहसानमंद होगी. ■

अपूर्व केशरवानी

छत्तीसगढ़

नए सिपहसालार

राहुल नरोन्हा

नया प्रदेश अध्यक्ष. राज्य का नया प्रभारी. अगस्त के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के छत्तीसगढ़ के संगठन में आमूल-चूल बदलाव देखा जा रहा है. राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में साल भर से थोड़ा ही अधिक समय बचा है और पार्टी ने अपनी तैयारियों में तेजी लाने के लिए तीन नए कंधों पर जिम्मेदारी डाली है. तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल के निर्बाध कार्यकाल के बाद भाजपा को 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था. वह 90 में से सिर्फ 15 सीटें जीतने में सफल रही, और बाद में हुए उपचुनाव में एक और सीट कांग्रेस के हाथों गंवा दी.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई में बड़े फेरबदल किए हैं. सबसे पहले, अगस्त की शुरुआत में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को छत्तीसगढ़ भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. साव 2019 में बिलासपुर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे. कुछ दिनों बाद, धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया. एक महीने के भीतर, डी. पुरंदेश्वरी की जगह भाजपा के पुराने दिग्गज ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया.

इस संगठनात्मक बदलाव का एक स्पष्ट मकसद है अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दिल जीतना. ओबीसी की राज्य की आबादी में हिस्सेदारी 40 फीसद से ज्यादा है और उसका कांग्रेस के प्रति झुकाव रहा है, जबकि साव उस साहू समुदाय से हैं, जिसे राज्य का सबसे बड़ा ओबीसी समूह माना जाता है. चंदेल एक अन्य ओबीसी कुर्मी समुदाय से आते हैं. हालांकि, अंदरखाने यह चर्चा धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है कि भाजपा तीन बार के पूर्व सीएम और राज्य में पार्टी के सबसे बड़े नेता रमन सिंह के करीबियों की जगह दूसरे नेताओं पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है. कहा जाता है कि साय और कौशिक, दोनों को रमन सिंह का समर्थन प्राप्त था.

2018 की चुनावी हार के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ में नए और युवा चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती थी. यह तीन साल पहले साफ हो गया था, जब 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए रमन सिंह के बेटे अभिषेक सहित सभी 10 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया था. इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साव उन नए चेहरों में से एक हैं, जिन पर पार्टी ने पहले लोकसभा का टिकट देते समय विश्वास जताया था और अब राज्य इकाई के प्रमुख के लिए भी उन्हें चुना है. पार्टी के एक राज्य स्तरीय पदाधिकारी बताते हैं, ''केंद्रीय नेतृत्व ने रमन सिंह का करीबी न माने जाने वाले नेताओं को नियुक्त करके स्पष्ट संदेश दिया है कि वह नए विकल्प तलाशने का इच्छुक है.'' हालांकि, वे यह भी मानते हैं कि राज्य की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री की पारी अभी खत्म नहीं हुई है. वे कहते हैं, ''वास्तव में, नए पदाधिकारियों के कौशल पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या वे पार्टी के भीतर सभी को साथ लेकर आगे चल सकने में सक्षम रहते हुए सच्चे नेता के रूप में उभर पाते हैं.''

भाजपा ने छत्तीसगढ़ इकाई में नेतृत्व परिवर्तन किया है, लेकिन क्या तीन बार मुख्यमंत्री रहे डॉ. रमन सिंह को अनदेखा किया जा सकता है?

हालांकि, पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग इस नेतृत्व परिवर्तन को रमन सिंह को किनारे लगाने के एक कदम के रूप में देखता है. यहां तक कि जब वे हाल ही में एक छोटी-सी सर्जरी के लिए दिल्ली गए, तो राज्य के राजनैतिक हलके

में ये अफवाहें फैलने लगीं कि उन्हें छत्तीसगढ़ से दूर रखने के लिए राज्यपाल बनाया जा रहा है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी पद संभाल रहे रमन सिंह ने *इंडिया टुडे* से बातचीत में इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, ''सत्ताधारी पार्टी [कांग्रेस] नियमित रूप से ऐसी कहानियां गढ़ती आ रही है कि मेरी छत्तीसगढ़ से विदाई हो रही है और उन कहानियों को मीडिया में भी चलवाती है. मैं पार्टी [भाजपा] का एक वफादार सिपाही हूं और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा.''

लेकिन अगर भाजपा रमन सिंह को हाशिए पर डाल दे तो फिर वह कहां खड़ी होगी? राज्य भाजपा के भीतर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि सीएम भूपेश बघेल से मुकाबला करने के लिए अभी भी पार्टी के पास रमन सिंह से बेहतर कोई चेहरा नहीं है. एक भाजपा विधायक कहते हैं, ''रमन सिंह शायद राज्य के एकमात्र नेता हैं जिनकी पूरे छत्तीसगढ़ पर पकड़ है. 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास नेताओं की एक पीढ़ी को विकसित करने का समय मिला और उन्होंने किया भी. उनकी अनदेखी करना आसान न होगा.''

सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए भी रमन सिंह स्पष्ट रूप से विपक्ष का एकमात्र चेहरा हैं. राजनैतिक विश्लेषक अशोक तोमर कहते हैं, ''भाजपा के नया प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता नियुक्त करने के बाद भी सीएम के निशाने पर हमेशा रमन सिंह ही होते हैं. इसी तरह, वे अकेले ऐसे नेता हैं जो सीएम को टक्कर देते हैं. यहां भाजपा के पास न तो आदिवासी और न ही ओबीसी समुदाय से कोई दूसरा ऐसा नेता है, जिसका कद इतना बड़ा हो.''

विधानसभा चुनाव से पहले, छत्तीसगढ़ में अगले छह महीने में भानुप्रतापपुर में उपचुनाव होने वाला है. यह आदिवासी बहुल सीट बस्तर क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां से भाजपा ने 2023 में चुनावी फायदे की उम्मीद लगा रखी है. 2018 के बाद से राज्य में हुए सभी चार उपचुनावों में कांग्रेस जीती है. आगामी उपचुनाव भाजपा के नए नेतृत्व के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा जो बताएगा कि प्रदेश में भाजपा के नए सिपहसालार आगे की बड़ी चुनावी लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं.■

जम्मू-कश्मीर

फीका पड़ता उम्मीद का फल

मोअज्जम मोहम्मद

कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एक अजीब-सी मायूसी पसरती जा रही है. दिन में अपने सेब के बागान से बाहर आपको शायद ही कोई मिले. इस साल बंपर फसल हुई है और किसान उसे तोड़ने में मसरूफ हैं. जम्मू-कश्मीर के बागवानी महकमे और किसानों का भी दावा है कि इस बार सेब की पैदावार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लेकिन किसान अपनी मेहनत के फल का पूरा फायदा न उठा सकेंगे. 10,000 करोड़ रुपए का बागवानी क्षेत्र कई समस्याओं से घिरा है, जिसमें सप्लाइ चेन में आ रहीं रुकावटें, महंगाई, कोल्ड स्टोरेज और कामगारों की कमी के साथ ईरानी सेब का आयात भी शामिल है. सेब की खेती में सीधे तौर पर 7,00,000 परिवार और परोक्ष रूप से यही कोई 35 लाख परिवार जुड़े हैं. यह कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करता है.

घाटी में सेब की टोकरी कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर के शोपियां के सेब किसान मुश्ताक अहमद मलिक कामगारों की कमी और ढुलाई में देरी जैसी दोहरी मार झेल रहे हैं. मलिक के पास उनके गांव पन्नू में 40 कनाल का बाग है लेकिन उन्हें सेब तोड़ने, छांटने और पैक करने के लिए 10 मजदूरों को रोज 10,000 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है. लगभग 1,000 पेड़ों से मलिक सेब के 4,000 बक्से (17 किलो प्रत्येक) तैयार कर लेते हैं. इस साल फसल में 150 फीसद की बढ़ोतरी

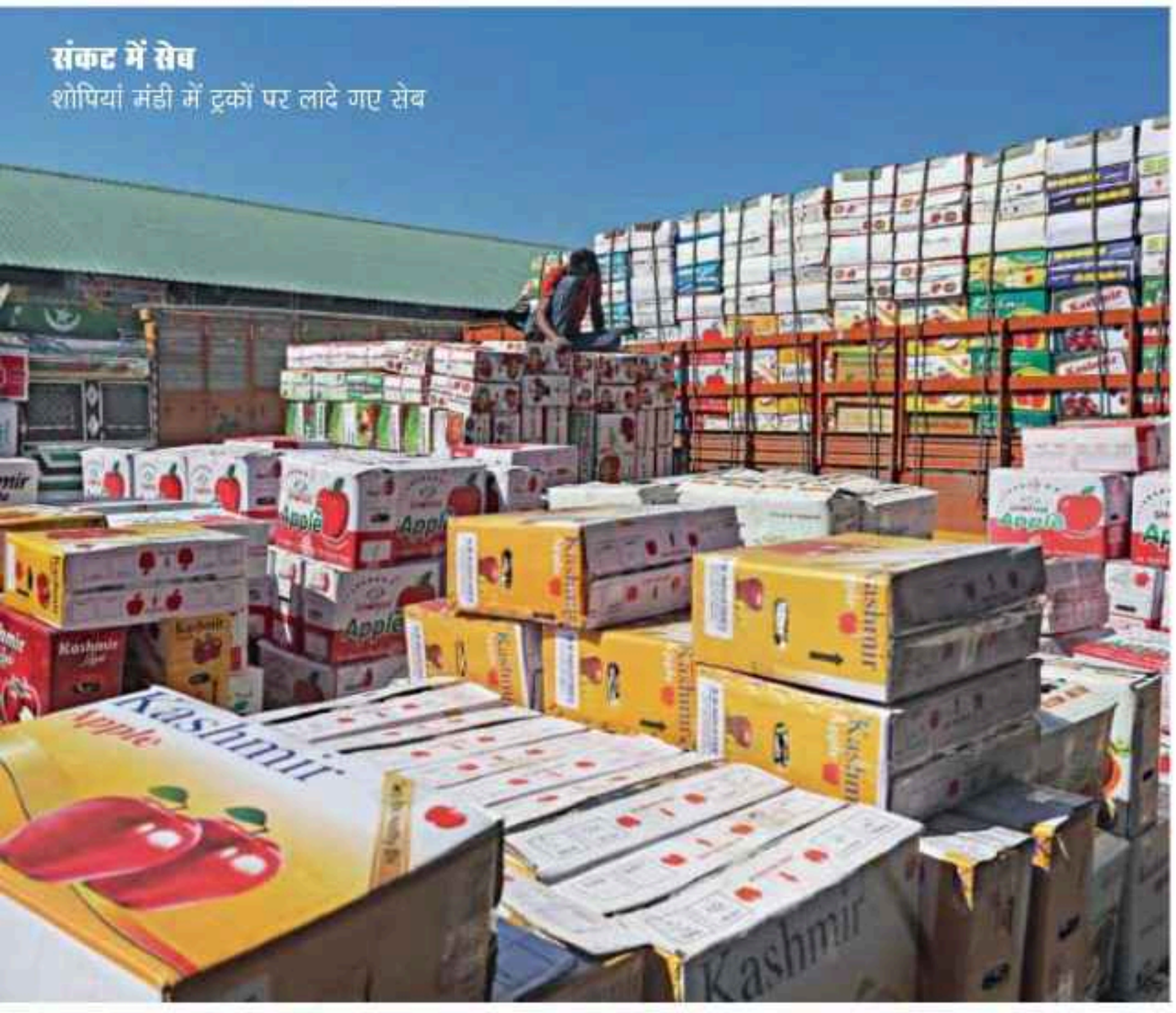

संकट में सेब
शोपियां मंडी में ट्रकों पर लादे गए सेब

होने की उम्मीद है. हालांकि वे इससे उत्साहित नहीं हैं. वे कहते हैं, ''फिलहाल एक युद्ध जैसी स्थिति दिखती है. मजदूरों और पैकेजिंग सामग्री आदि के लिए मारामारी है. कीमतें आसमान छू रही हैं पर मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं है.'' इस महीने की शुरुआत में उनकी दो खेप दिल्ली में औने-पौने दामों पर बिकीं.

सितंबर में जैसे ही तुड़ाई शुरू हुई, फलों से लदे हजारों ट्रक घाटी से भारत के विभिन्न राज्यों के लिए रवाना हुए. लेकिन उन्हें जोखिम भरे पहाड़ी श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के किनारे अधिकारियों ने कई दिनों तक रोक दिया. मलिक की खेप को दिल्ली की आजादपुर मंडी तक पहुंचने में सात दिन लगे. वैसे, 900 किमी से कम की दूरी तय करने में दो दिन ही लगते. फल खराब हो गए थे; इसलिए उन्हें एक बॉक्स के केवल 650-700 रुपए ही मिले. आमतौर पर इसके 1,200 रुपए या उससे अधिक मिलते हैं. उत्पादकों के अनुसार, सेब का एक बॉक्स तैयार करने पर 500 रुपए का खर्च आता है जिसमें माल भाड़ा शामिल नहीं है. कीमतों में गिरावट क्यों आई? सेब रास्ते में सड़ गए और एक ही दिन मंडियों में सेब से लदी बहुत ज्यादा गाड़ियों के पहुंचने से भी मांग में कमी आई.

किसानों का आरोप है कि उन्हें नुक्सान पहुंचाने के लिए ट्रकों को 'जान-बूझकर' रोका गया. विरोधस्वरूप उन्होंने 25 सितंबर से दो दिन के लिए पूरे कश्मीर की मंडियों को बंद कर दिया. जम्मू-कश्मीर प्रशासन हरकत में आया और राजमार्ग के रामबन सेक्टर के एसएसपी (यातायात) को हटा दिया. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ट्रकों को कश्मीर के काजीगुंड में रोका गया था क्योंकि संकरे इलाके और चल रहे निर्माण के कारण दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को सुचारु रखने के लिए किसी भी दिन एक साथ दोनों तरफ का रास्ता नहीं खुलता बल्कि बारी-बारी से एक दिन के लिए रास्ता खोला जाता है.

कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स-कम-डीलर यूनियन (किसान सह विक्रेता संघ) के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर का कहना है कि इस साल किसानों, खरीदारों और कारोबारियों को जितना बड़ा झटका लगा है, उतना शायद ही कभी लगा हो. उनके अनुसार, फल की कोई मांग ही नहीं है क्योंकि मंडियों में पहले से ही काफी स्टॉक पड़ा है. वे कहते हैं, ''हम यकीन से नहीं कह सकते कि राजमार्ग की नाकाबंदी ने या मौसम या फिर अत्यधिक पैदावार ने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया है. नुक्सान की भरपाई में कई साल लगेंगे.''

बशीर की मांग है कि सरकार को कम गुणवत्ता वाले सेब खरीदने चाहिए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके. उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए 4 अक्तूबर को श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. तब से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन की ओर से कई उपाय किए गए हैं और मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

एनएच पर लंबे समय तक ट्रकों के रुकने का असर निर्यातकों पर भी पड़ा है. फ्रूट मास्टर एग्रो फ्रेश जेएंडके फर्म चलाने वाले पुलवामा के 28 वर्षीय उद्यमी इजहान जाविद ढुलाई में देरी से दुखी हैं, उनका यूएई स्थित रिटेल दिग्गज लूलू समूह के साथ सेब सप्लाइ का एक करार है. वे बताते हैं कि उन्होंने इस सीजन में यूएई को छह कंटेनर भेजे हैं, जबकि 2-3 अभी भी रास्ते में हैं. एक कंटेनर को मुंबई पोर्ट तक पहुंचने में 8-10 दिन लग गए. वे श्रीनगर राजमार्ग पर देरी को कीमतों में गिरावट के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार मानते हुए बताते हैं, ''कंटेनरों को मुंबई तक पहुंचने में इतना समय लग गया जबकि वे दुबई केवल चार दिन में पहुंच गए.'' जाविद मुक्त व्यापार समझौते के तहत ईरान से आयात किए जा रहे शुल्क मुक्त सेब और महामारी के बाद की वैश्विक मंदी को नुक्सान की दूसरी वजहें मानते हैं. समुद्री मार्गों और अफगानिस्तान के रास्ते अटारी-वाघा सीमा से बड़ी खेप भेजी जा रही है, जिससे घरेलू बिक्री प्रभावित हो रही है.

सेब किसान कई मोर्चों पर मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जिनमें सप्लाइ चेन की रुकावटें और कोल्ड स्टोरेज तथा मजदूरों की कमी शामिल है

जाविद का कहना है कि किसान फलों का स्टॉक कर सकते थे ताकि कीमतें बढ़ने (मार्च-अप्रैल) पर इसे बेचकर मुनाफा बना सकें लेकिन पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज न होने से यह संभव नहीं हो पा रहा. कश्मीर को 4 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता की जरूरत है, पर इसकी आधी से भी कम उपलब्ध है.

कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ऐंड टेक्नोलॉजी के प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉ. तारिक रसूल का कहना है कि हाइवे नाकेबंदी से ज्यादा, मैकेनाइज्ड बागवानी तकनीकों की कमी और बागों का पारंपरिक तरीके से बना होना किसानों का नुक्सान करा रहा है. यूरोप में एक किसान उन्नत कृषि मशीनरी का उपयोग करके लागत कम रखता है और एक यूरो प्रति किलो से कम पर सेब बेचता है. उन्हें प्रति हेक्टेयर 200-800 लीटर पानी के छिड़काव की जरूरत होती है जबकि कश्मीर में यह 4,000-8,000 लीटर है. पैदा करने की लागत ज्यादा होने की वजह से किसान 50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के रेट पर सेब बेचने को मजबूर हो जाते हैं. रसूल कहते हैं, ''लागत कम करने के लिए हमें मशीनों का प्रयोग करना चाहिए और छिड़काव के लिए ड्रोन जैसी तकनीक अपनानी चाहिए. ये तकनीकें लागत 45 फीसद तक घटाकर व्यापार को फायदेमंद बना सकती हैं.''

बागवानी विभाग के नियोजन और विपणन के उप निदेशक मंजूर अहमद मीर का कहना है कि हाइवे की दिक्कतों के अलावा, बाजारों में ज्यादा सप्लाइ और उचित छंटाई (आकार और गुणवत्ता के अनुसार) की कमी भी कीमतों में गिरावट के लिए जिम्मेदार है. उनका यह भी दावा है कि कोल्ड स्टोरेज में जगह की कमी के कारण भी किसान अपनी उपज को खराब होने से पहले औने-पौने दाम पर ही बेचने को मजबूर हैं. कश्मीर हर साल 19 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा करता है जिसमें से पिछले हफ्ते तक 9.60 लाख मीट्रिक टन सेब बाजारों में भेजा जा चुका था.

मीर का कहना है कि सरकार खरीदारों और किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाई है. लेकिन किसान पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर अंदेशे में हैं. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद के महीनों में सरकार ने सेब की मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए बाजार मूल्य हस्तक्षेप योजना शुरू की थी. इसमें किसानों से 12 लाख मीट्रिक टन सेब की सीधी खरीद शामिल थी. इसका उद्देश्य किसानों के मुनाफे को 2,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना था. मीर कहते हैं, ''उन्हें हरेक सेंटर पर 20-25 कर्मचारियों और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करनी पड़ती थी. इस पर भारी लागत आई.'' मीर के अनुसार, पांच संग्रह केंद्रों से केवल 15,800 मीट्रिक टन सेब ही उठाए गए, जिससे यह योजना बंद हो गई. फिलहाल, घाटी के सेब बड़ी मुसीबत में हैं.■

झारखंड / हेमंत सोरेन

आर या पार की तकरार

अमिताभ श्रीवास्तव

चुप्पी की चुनौती
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 अक्तूबर को राज्यपाल रमेश बैस के साथ

सौमनाथ सेन

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर छाए संकट के बादल न तो छंटते दिख रहे हैं, न ही बरसते. बीते 25 अगस्त को जब भारत के चुनाव आयोग ने कथित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में विधायक के रूप में हेमंत की अयोग्यता के बारे में अपनी राय राज्यपाल को भेजी, तब से उनकी विधानसभा सदस्यता और मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता बनी हुई है. राज्यपाल रमेश बैस ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर दो महीने की चुप्पी तोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने इस मामले में 'दूसरी राय' मांगी है. दीवाली के बाद अपने गृहनगर रायपुर में मीडिया से बात करते हुए बैस ने संकेत दिया कि ''झारखंड में कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है.''

इस मामले में हो रही देरी को सरकार को अस्थिर करने की ''सोची-समझी चाल'' के रूप में देखने वाला सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) राज्यपाल के इस बयान से और उत्तेजित हो गया है. झामुमो का कहना है कि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में 'दूसरी राय' का कोई संदर्भ नहीं है.

इससे पहले, 15 अक्तूबर को राज्य की राजधानी रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए सोरेन ने कहा था, ''आज मैं जिस स्थिति में हूं, महामहिम की चुप्पी मेरे लिए सजा से कम नहीं है.'' मुख्यमंत्री ने अपनी स्थिति की तुलना उस संदिग्ध व्यक्ति से की जो कह रहा हो कि 'अगर मैं दोषी हूं, तो मुझे दंडित किया जाए.'

झारखंड में यह गड़बड़ इस साल फरवरी में शुरू हुई जब राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्यपाल बैस से संपर्क कर आरोप लगाए कि सोरेन के पास खनन पट्टा होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है. निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार के साथ किसी वस्तु की आपूर्ति या कोई भी सरकारी काम करने का अनुबंध नहीं कर सकते. 2021 में खनन पट्टा हासिल करने वाले सोरेन ने सियासी हंगामे के बाद फरवरी में उसे वापस कर दिया था. लेकिन तब तक बैस ने सोरेन को अयोग्य ठहराए जाने की भाजपा की याचिका को चुनाव आयोग के पास भेज दिया था.

चुनाव आयोग के कथित पत्र के बीच उन्हें अनिवार्य रूप से अयोग्य ठहराए जाने की खबरें सामने आने के बाद सोरेन अतिसक्रिय हो गए. उन्होंने 30 अगस्त को सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के 32 विधायकों को कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ भेज दिया ताकि उन्हें 'अवैध तरीकों' से अपने साथ मिलाने के भाजपाई प्रयासों को रोका जा सके. बाद में उन्होंने इन विधायकों को वापस बुलाया और 5 सितंबर को विधानसभा में एकतरफा विश्वास प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव के समर्थन में 48 मतों और विरोध में शून्य मतों के साथ मुख्यमंत्री ने आराम से प्रस्ताव पारित करा लिया. इस मौके पर भाजपा ने सदन से बहिर्गमन किया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के बीच में ही पद से हटाए जाने की स्थिति में वापसी का आधार तैयार करने वाले कई लोकलुभावन फैसले किए हैं.

इस दौरान, टीम सोरेन ने चुनाव आयोग की सिफारिशों के बारे में जानकारी हासिल करने के कई प्रयास किए हैं. मुख्यमंत्री ने सितंबर में राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे अपनी अयोग्यता पर बने रहस्य को खत्म करने का आग्रह किया. उनकी कानूनी टीम ने भी चुनाव आयोग से संपर्क कर बैस को भेजे गए पत्र की एक प्रति मांगी जबकि पार्टी के एक नेता ने आयोग की राय जानने के लिए सूचना के अधिकार का सहारा लिया. लेकिन ये सभी प्रयास निष्फल रहे हैं.

झारखंड के एक वरिष्ठ नौकरशाह कहते हैं कि ''सोरेन के पास नाराज होने का वास्तविक कारण है. वे देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें रात को सोने जाते समय यह नहीं पता होता कि अगली सुबह जागने पर वे अपने पद पर मौजूद होंगे या उनके पदनाम के आगे 'पूर्व' लगा होगा.'' नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर बने झारखंड का इतिहास ऐसी अनिश्चितताओं से भरा रहा है. दिसंबर 2014 में भाजपा के रघुबर दास के बागडोर संभालने और मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करने वाला पहला मुख्यमंत्री बनने के पहले तक इस नवस्थापित राज्य ने नौ सरकारें और राष्ट्रपति शासन के तीन दौर देखे थे.

दिसंबर 2019 में भाजपा से सत्ता छीनने वाले सोरेन के पास पर्याप्त बहुमत वाला गठबंधन है. कुल 82 सदस्यों के सदन में उनके नेतृत्व वाले झामुमो के 30 सहित गठबंधन में कुल 49 विधायक हैं. लेकिन माना जा रहा है कि अयोग्य ठहराए जाने की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री उधार के समय पर कार्यरत हैं. सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बने रहने की स्थिति में उनके लिए बहुत से नीतिगत निर्णय लेना अनिवार्य होता है. हालांकि उन्हें पद से हटाए जाने की स्थिति में इन निर्णयों की वैधता न्यायिक जांच के दायरे में आ सकती है. लगता है कि अगर इस सियासी नाटक को निष्कर्ष तक पहुंचने में और समय लगता है, तो स्थिति और खराब हो जाएगी. ■

विधानसभा सदस्यता की अयोग्यता के मामले में देरी से परेशान सोरेन का कहना है कि अगर वे दोषी हैं तो उन्हें दंडित किया जाए

सुर्खियां

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

समाचार सार

बड़ी बहन

लगता है कि दीदी ममता बनर्जी गलती करने वाले अपने 'भाइयों' को माफ कर देंगी. शायद इसलिए 2017 से 2021 के बीच भाजपा के साथ रहे अनुभवी पार्टी नेता मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के 'भाई फोन्टा' समारोह में आमंत्रित किया गया. ऐसा ही बुलावा दलबदलू शोभन चटर्जी को भी मिला जो थोड़े वक्त तक भगवा पार्टी के करीब रहे थे. एक दौर में ममता ने इन दोनों को गद्दार बताया था, पर लगता है कि उन्होंने इन नेताओं को फिर से अपने करीबियों में शामिल करने का मन बना लिया है. तो क्या इस समय भाजपा में शामिल शुभेंदु अधिकारी की भी टीएमसी में ऐसे ही पुनर्वास की गुंजाइश है?

गड्ढों पर ध्यान

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं. इसके लिए उन्होंने 15 नवंबर की समयसीमा भी तय की है. इसके बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि कई भाजपा विधायकों ने भी गड्ढों की तस्वीरें और वीडियो अफसरों को भेजना शुरू कर दिया. इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री **जितिन प्रसाद** ने जांच के लिए खुद अभियान पर निकलने का फैसला किया. पर अधिकारी ज्यादा होशियार साबित हुए. उन्होंने प्रसाद के कार्यालय से उन क्षेत्रों की सूचना पाने के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया, जहां उनका "आकस्मिक निरीक्षण" के लिए जाना संभावित है ताकि वे मंत्री के आने से पहले गड्ढों को ठीक करवा सकें.

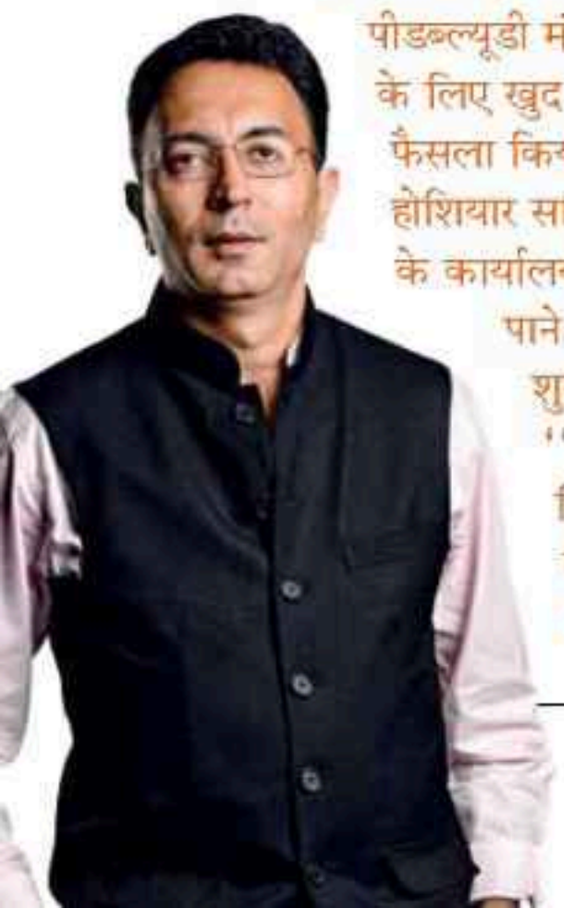

विक्रम शर्मा

अपना विज्ञापन

मध्य प्रदेश में 31 अक्तूबर को स्थानीय अखबारों में विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक **संजय पाठक** का एक पूरे पन्ने का विज्ञापन देखने को मिला. उनके जन्मदिन पर प्रकाशित इस विज्ञापन में उनके क्षेत्र में उनके लोक कल्याणकारी कार्यों और उनके परिवार के प्रति वोटरों के सम्मान का उल्लेख था. खनन क्षेत्र का यह महारथी 2014 में कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आया और उन्हें मंत्री पद मिला था. पर पार्टी ने 2020 में सत्ता में वापसी की, तो उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली. 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना के मद्देनजर क्या पाठक कोई इशारा कर रहे हैं?

नकल का सिद्धांत

राजस्थान के मुख्यमंत्री **अशोक गहलोत** को इन दिनों इंदिरा रसोई में खाना खाते देखा जा सकता है, जहां कोई भी 8 रुपए में भोजन कर सकता है. इस भोजन पर राज्य सरकार 17 रुपए की सब्सिडी देती है. कुल 14 करोड़ रुपए के बजट के साथ ऐसी 870 रसोइयां चल रही हैं, जो मार्च तक 1,000 हो जाएंगी. गहलोत ने स्थानीय नेताओं से भी यहां भोजन करने का आग्रह किया है. 'सम्मान के साथ भोजन' का गहलोत का नारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की 'सचल अन्नपूर्णा रसोई' से लिया गया है. गहलोत ने पहले इसको रोक दिया था, पर शायद फिर उन्हें लगा कि वोटरों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है.

मोकामा से दूरी

आखिरकार सुशासन बाबू उपचुनाव का प्रचार करने मोकामा नहीं गए. वहां से महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर **नीलम देवी** चुनाव लड़ रही हैं. वे बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं. सीएम नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में कदम रखने की तैयारी में हैं तो वे फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं. इसलिए वे एक कांड में दोषी और सजा पाने वाले अनंत सिंह की पत्नी के लिए मैदान में नहीं उतर पा रहे. वैसे, उन्होंने वीडियो जारी कर नीलम देवी का प्रचार किया, मगर वह एक औचारिकता भर थी.

—कौशिक डेका, *साथ में* रोमिता दत्ता, रोहित परिहार, प्रशांत श्रीवास्तव, राहुल नरोन्हा *और* पुष्यमित्र

जनता के बीच
प्रतिभा सिंह शिमला के चौपाल में चुनाव प्रचार के दौरान

विधानसभा चुनाव 2022
हिमाचल प्रदेश

पहाड़ की 'पथरीली' राह

हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, क्या यहां के मतदाता सरकार बदलने की परंपरा तोड़ते हुए भाजपा को दूसरा कार्यकाल देंगे, या फिर कुर्सी कांग्रेस को मिलेगी?

अनिलेश एस. महाजन, शिमला से

का रों का काफिला जैसे ही हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सड़क से नीचे उतरता है, फूल-मालाओं से लदीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने समर्थकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कार से उतरती हैं. छह बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, घुमारवीं सीट से पार्टी के उम्मीदवार राजेश धर्माणी के लिए प्रचार करने यहां पहुंची हैं. बिलासपुर प्रतिद्वंद्वी भाजपा का गढ़ है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का घर भी. इसलिए कांग्रेस इस क्षेत्र में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रही है. पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, शायद यही वजह है कि प्रतिभा सिंह चुनाव अभियान में अपनी तरफ से अतिरिक्त प्रयास कर रही हैं. अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए वे प्रमुख दावेदार होंगी.

राज्य विधानसभा के 68 सदस्यों को चुनने के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है. 1985 के बाद से किसी भी पार्टी ने दोबारा जनादेश हासिल नहीं किया है जिससे कांग्रेस की उम्मीदों को बल तो मिलता है लेकिन इस चुनाव में उसे वीरभद्र सिंह और उनके संगठनात्मक कौशल की कमी विशेष रूप से खटकेगी. हिमाचल चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहम हैं. कांग्रेस काफी समय से देश में लगातार चुनाव हारती आ रही है और हिमाचल से वह अपनी हार पर विराम लगाने की उम्मीद कर रही होगी. यह पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी एक शानदार स्वागत उपहार होगा. वहीं, भाजपा के नड्डा, जिन्होंने जनवरी में पार्टी प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल/विस्तार पर नजर गड़ा रखी है, के लिए हिमाचल का अनुकूल परिणाम उनकी दावेदारी को मजबूत करेगा.

इस बीच प्रतिभा हर दिन 4-5 रैलियों को संबोधित कर रही हैं. जैसा कि अपेक्षित है, बातचीत ज्यादातर ''राजा साहब'' और राज्य में उनके योगदान के इर्द-गिर्द घूमती है. उनके दिवंगत पति को प्यार से ''राजा साहब'' के नाम से जाना जाता था. वीरभद्र की जुलाई 2021 में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी. उनकी मृत्यु से पैदा हुई सहानुभूति की लहर पिछले साल के उपचुनावों के दौरान कांग्रेस के लिए फायदेमंद रही और जनता ने सभी तीन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों और मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा को जिता दिया. हालांकि, चुनावी पंडित इस बात को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आते कि आगामी चुनाव में भी वही माहौल दिखेगा. लेकिन राजा साहब के पुत्र और शिमला ग्रामीण सीट से मौजूदा विधायक विक्रमादित्य सिंह आश्वस्त नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में धामी के पास परिहाना गांव के लिए ट्रैक के दौरान *इंडिया टुडे* से बातचीत करते हुए, उन्होंने बताया, ''पार्टी चाहती है कि वे स्वतंत्र रूप से प्रचार करें और खुद को केवल एक सीट तक सीमित न रखें.''

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आश्वस्त हैं कि उनके कांग्रेसी प्रतिद्वंद्वियों को चुनाव में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे. वे कहते हैं, ''उनके सबसे प्रसिद्ध नेता अब नहीं रहे. कांग्रेस बिखरी हुई है और इससे भाजपा को फायदा होने वाला है.'' उन्हें विश्वास है कि वे इस बार राज्य में मौजूदा पार्टी को दोबारा जनादेश नहीं मिलने की पुरानी परिपाटी को तोड़ने में सफल होंगे. पार्टी के नए चुनावी नारे का हवाला देते हुए वे कहते हैं, ''हम रिवाज बदलेंगे.''

बागियों का बल

मुख्यमंत्री ठाकुर भले ही यह कहने से बचें लेकिन उनकी पार्टी भी बागियों से त्रस्त है. टिकटों का बंटवारा पूरा हो जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब सीएम ही पहाड़ियों के नए क्षत्रप हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल

संदीप सहदेव

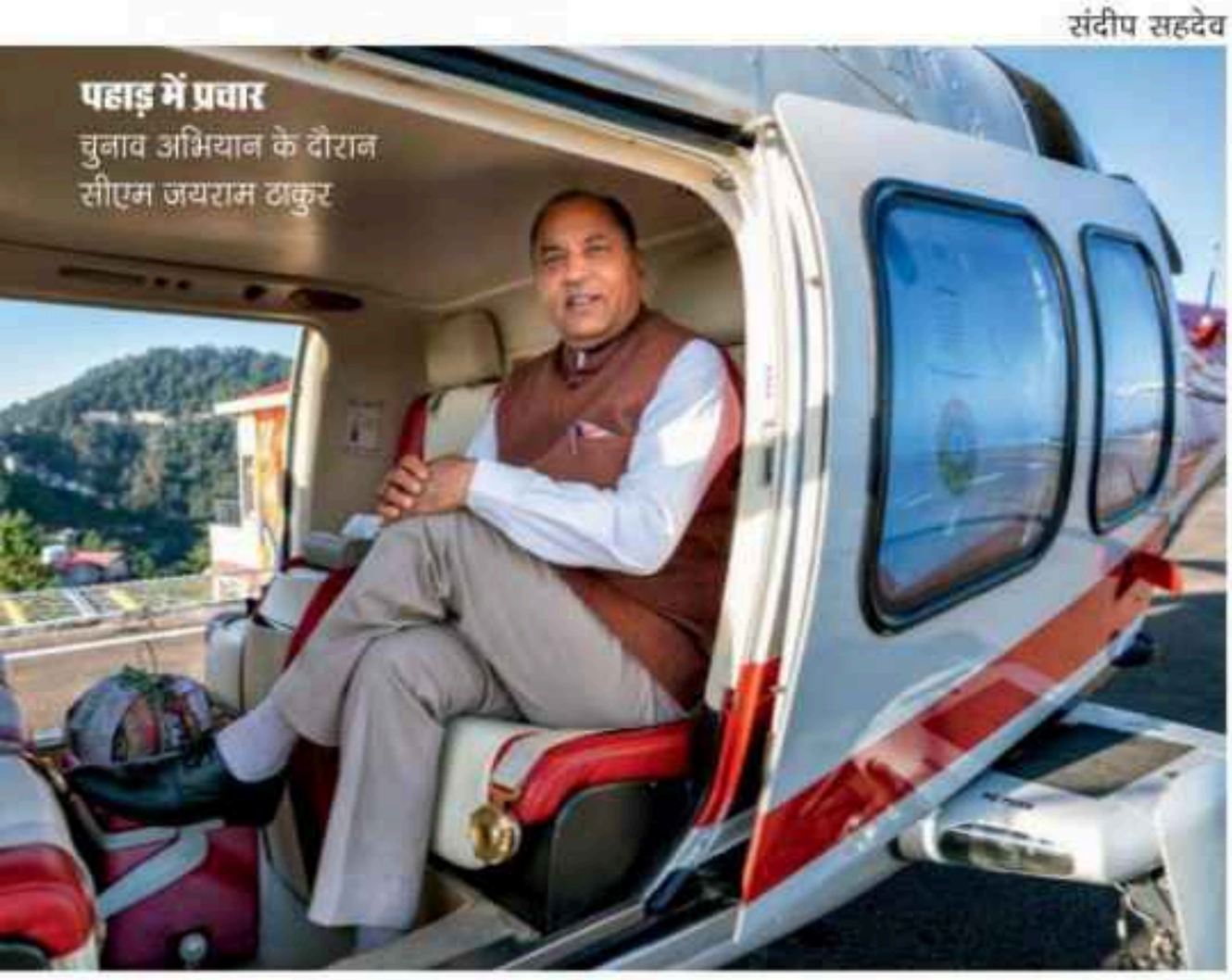

पहाड़ में प्रचार
चुनाव अभियान के दौरान सीएम जयराम ठाकुर

के समर्थक घट चुके हैं. भाजपा ने इस बार 23 नए चेहरों पर दांव लगाया है और उसे 14 सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है. पांच नेताओं को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है, जिनमें चार पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद कृपाल परमार शामिल हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि बागी 5-6 सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं.

कांग्रेस के लिए मुसीबत और गहरी है. विद्रोहियों में से कई कभी वीरभद्र खेमे के हुआ करते थे. भाजपा पहले ही प्रतिभा सिंह के मुख्य रणनीतिकार और हिमाचल कांग्रेस के पूर्व प्रमुख हर्ष महाजन को अपने पाले में कर चुकी है. परिवार के एक अन्य वफादार पवन काजल अब कांगड़ा से भाजपा के उम्मीदवार हैं. टिकट से वंचित कुछ अन्य नेता भी बगावत पर उतारू हैं. इसके अलावा, कुलदीप सिंह राठौड़, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं के भी अपने अलग गुट हैं. सभी खेमों को एकजुट करने के लिए पार्टी ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की और उसी समझौते के तहत सुक्खू को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया और अग्निहोत्री को विपक्ष के नेता के रूप में बरकरार रखा गया. लेकिन स्थिति समझौते से कोसों दूर है.

दोनों ही पार्टियों के बागी उनकी संभावनाओं को बिगाड़ सकते हैं. 2017 में, 20 सीटों पर जीत का अंतर 3,000 वोटों से कम और छह सीटों में 1,000 से कम था. भाजपा को 48.8 फीसद वोट मिले, कांग्रेस को 41.7 फीसद (2012 की तुलना में सिर्फ 1.1 फीसद की गिरावट), और छोटी पार्टियों को 9.5 फीसद वोट मिले. भाजपा पहले से ही यह कह रही है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी (आप) अपनी जमीन भी नहीं बना सकी है, जिससे कांग्रेस के वोटों में विभाजन हो सकता था. इसलिए पार्टी को अब अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

रेवड़ी बनाम कल्याणकारी योजनाएं

आप से प्रेरणा लेते हुए, हिमाचल में कांग्रेस ने 10 गारंटी दी हैं जिनमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, राज्य में प्रत्येक वयस्क महिला (18 से ऊपर) के लिए 1,500 रुपए की सहायता आदि लोकलुभावन वादे शामिल हैं. इसके साथ ही, प्रतिभा ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पहली कैबिनेट बैठक में फिर से पेश किया जाएगा. हिमाचल में राज्य सरकार के 3,00,000 कर्मचारी हैं और यह तबा कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला जिलों में परिणाम को प्रभावित कर सकता है.

अपनी-अपनी ताकत

कांग्रेस

- राज्य में जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर
- भाजपा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पी.के. धूमल गुटों के बीच खींचतान
- चुनावी वादे : सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन, स्टार्ट-अप के लिए 640 करोड़ रुपए का फंड, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना

भाजपा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदूवादी और राष्ट्रवादी छवि की मतदाताओं के बीच व्यापक स्वीकार्यता
- केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना
- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपेक्षाकृत साफ-सुथरी छवि
- पार्टी की चाक-चौबंद चुनावी मशीनरी

2017 का विधानसभा चुनाव
कुल सीटें: 68

इस बीच, ठाकुर का तर्क है कि उनकी सरकार पहले से ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, जिसका लाभ राज्य के कुल 14 लाख उपभोक्ताओं में से 11 लाख, पहले से ही ले रहे हैं. भाजपा शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति को भी मुफ्त कर दिया है, और सरकारी बसों में महिला यात्रियों को 50 प्रतिशत की छूट दी है. पार्टी महिला मतदाताओं के बीच यह बात जोर-शोर से उठा रही है कि केंद्र और राज्य की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से कैसे सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलता है.

किसके पक्ष में क्या है

कांग्रेस का मानना है कि वीरभद्र परिवार के प्रति सहानुभूति के साथ-साथ राज्य के दूर-दराज के हिस्सों में भी पार्टी की संगठनात्मक उपस्थिति उसके पक्ष में काम करेगी.

इस बीच, भाजपा पीएम मोदी और एक राष्ट्रवादी हिंदू वोटों की अपील पर वापस आ रही है. जैसा कि एक विश्लेषक कहते हैं कि हिमाचल एक 'अति हिंदूवादी मानसिकता' वाला राज्य है और यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी मोदी या अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे उसके कुछ 'राष्ट्रवादी' कदमों की आलोचना करने से बचते हैं. पीएम के करिश्मे के अलावा, भाजपा को अपने अच्छे चुनावी प्रबंधन का भी लाभ मिलेगा.

भाजपा अपने बूथ प्रबंधन के जरिए गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर तक में सत्ता विरोधी लहर को काबू कर बेहतर नतीजे हासिल पा चुकी है. पार्टी अब यह प्रयोग हिमाचल प्रदेश में भी करने जा रही है. सेना के अंदाज में शत्रु की घेराबंदी का उसका यह प्रयास सफल रहा या विफल, इसका पता तो आगामी 8 दिसंबर को ही चलेगा. ■

राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री

केरल और अन्य राज्यों की सरकारों से टकराव ने राज्यपालों की भारतीय संघीय ढांचे में भूमिका की पुरानी बहस को एक बार फिर ताजा कर दिया

कौशिक डेका

रल ऐसे ही तजुर्बे से पहले भी गुजर चुका है. बहुत पहले 1959 में तब भाकपा (और बाद में माकपा) के दिग्गज नेता ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद की अगुआई वाली सरकार और राज्यपाल बी.आर. राव के बीच तलवारें खिंच गई थीं. मुद्दे कई थे, पर मुख्य तकरार उस शिक्षा विधेयक को लेकर थी जिसका मकसद निजी शिक्षा क्षेत्र में कुछ सुधार लागू करना था. राज्यपाल इस विवादास्पद विधेयक को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं थे. कई संगठन और दबाव समूह भी इसका विरोध कर रहे थे. टकराव का नतीजा आखिरकार यह हुआ कि नंबूदिरीपाद की सरकार बर्खास्त कर दी गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. छह दशक से भी ज्यादा वक्त बाद इस दक्षिणी राज्य में पिनरई विजयन की अगुआई वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) की सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच ऐसा ही टकराव देखने को मिल रहा है. इस बार भी झगड़े की जड़ शिक्षा क्षेत्र है. साफ कहें तो केरल सरकार के 13 विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति का मसला है.

अक्तूबर की 17 तारीख को खान ने राज्य के मंत्रियों को यह चेतावनी देकर राजनैतिक विवाद छेड़ दिया कि अगर उन्होंने राजभवन की ''गरिमा गिराना'' जारी रखा तो वे उन्हें हटाने से नहीं हिचकेंगे. फौरी उकसावा उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु का वह बयान था जिसमें उन्होंने राज्यपाल से उपकुलपतियों की नियुक्ति में राजभवन के अधिकारों को कम करने वाले विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पर दस्तखत करने को कहा था. दो दिन पहले राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की हैसियत से राज्यपाल ने केरल विश्वविद्यालय की सीनेट के 15 सदस्यों को इसलिए हटा दिया था क्योंकि उन्होंने उपकुलपतियों की चयन समिति को अपने नामजद लोगों के नाम नहीं भेजे थे.

संघीय तकरार
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (बाएं से तीसरे) सीएम पिनरई विजयन (दाएं से दूसरे) के साथ

टकराव देखते ही देखते बड़े तूफान में बदल गया जब राज्यपाल ने राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से इसलिए इस्तीफे मांग लिए क्योंकि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था. चयन समिति को राज्यपाल की मंजूरी के लिए तीन नाम भेजने होते हैं, पर उन्होंने एक ही भेजा. राज्यपाल के इस आदेश से पहले सुप्रीम कोर्ट ठीक इसी आधार पर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वीसी के पद पर एम.एस. राजाश्री की नियुक्ति रद्द कर चुका था.

पिछले साल एक वीसी की नियुक्ति भी खान और पिनरई सरकार के बीच झगड़े की जड़ बन गई थी. तब राज्यपाल ने गोपीनाथ रवींद्रन को दोबारा कन्नूर विश्वविद्यालय का वीसी बनाने में अड़चनें डालीं. कड़वाहट तब तीव्र हो गई जब खान ने रवींद्रन को 'अपराधी' कहा, जिसने 2019 में खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की कथित साजिश रची थी.

उपकुलपतियों के खिलाफ उनके मौजूदा कदमों का कड़ा विरोध किया गया. इस्तीफा तो खैर किसी ने नहीं दिया, उलटे मुख्यमंत्री विजयन ने खान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों की सीमा न लांघें. जवाब में राज्यपाल ने उपकुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 नवंबर तक जवाब देने को कहा. उपकुलपति उनके निर्देश के खिलाफ केरल हाइकोर्ट चले गए.

एएनआइ

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपनी शक्तियों से परे जाने के खिलाफ चेतावनी दी है

केरल में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव ने भारत के संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका पर नए सिरे से तीखी बहस छेड़ दी है. पहले ऐसी बहसें राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में राज्यपाल के विवेकाधिकार को लेकर हुआ करती थीं. अब राज्यपाल और निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच टकराव दूसरे कामों को लेकर होने लगे हैं. मसलन, विधानसभा सत्र बुलाने का वक्त तय करना, रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज की जानकारियां मांगना, विधेयकों की मंजूरी में देरी करना या विधेयक राष्ट्रपति को भेज देना, और खुलेआम सरकार की आलोचना करना.

मिसाल के लिए, अक्तूबर में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी वापस लेकर विवाद छेड़ दिया. सत्र मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वास प्रस्ताव रखने के लिए बुलाया था. इसी तरह केरल और राजस्थान में भी 2020 में विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया. महाराष्ट्र में तब उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली सरकार का स्पीकर की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी के साथ टकराव हुआ. तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरों सरीखे मुद्दों पर भी राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बीच खुलेआम अप्रिय तनातनी हो चुकी है.

उपकुलपतियों को लेकर युद्ध

उपकुलपतियों की नियुक्ति न केवल केरल बल्कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब सरीखे दूसरे राज्यों में भी खास तौर पर विवाद का मुद्दा बनकर उभरी है. पंजाब में राज्यपाल पुरोहित ने लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वीसी के पद पर जाने-माने बायोटेक्नोलॉजिस्ट सतबीर सिंह गोसल की नियुक्ति को ''गैरकानूनी'' करार देते हुए मुख्यमंत्री मान से उन्हें तत्काल हटाने को

कह दिया. इस फरमान से एक हफ्ते पहले राज्यपाल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के फरीदकोट स्थित बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार के चयन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. राज्य सरकार ने हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. गुरप्रीत सिंह वंडर की नियुक्ति की थी, पर पुरोहित ने 11 अक्तूबर को इस नियुक्ति को खारिज करके उपकुलपतियों के चयन के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम भेजने को कहा.

ऐसे टकराव पहले भी हुए हैं, जब केंद्र में गैर-भाजपा सरकारें थीं. 1980 में तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेस नेता और तब केरल के राज्यपाल ज्योति वेंकटचलम ने मुख्यमंत्री ई.के. नयनार की इच्छा के खिलाफ जाकर केरल विश्वविद्यालय के वीसी के पद पर ए.वी. वर्गीज को नियुक्त कर दिया. करीब एक दशक पहले मुख्यमंत्री नयनार का एक अन्य राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा से भी पंगा हो गया था, क्योंकि सिन्हा ने कालीकट विश्वविद्यालय की सीनेट में कुछ नियुक्तियां कर दी थीं. 1984 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ए.पी. शर्मा ने कलकत्ता और बर्दवान विश्वविद्यालयों के लिए तब मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नामजद व्यक्तियों को खारिज करके कुछ अन्य लोगों को इन पदों के लिए चुना. नाराज बसु ने कुलाधिपति के अधिकारों में कटौती करते हुए संशोधन पारित किया जिस पर शर्मा ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया. आखिरकार केंद्र सरकार को शर्मा से इस्तीफा देने को कहना पड़ा. अगले साल तमिलनाडु के राज्यपाल एस.एल. खुराना ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के वीसी के पद पर एम.जी. रामचंद्रन की अगुआई वाली एआइएडीएमके की सरकार के सुझाए सी.ए. पेरुमल को नियुक्त करने से इनकार कर एस. कृष्णास्वामी की नियुक्ति कर दी थी.

ऐसे टकरावों की जड़ें उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर अपनी विचारधारात्मक पकड़ कायम करने के राजनैतिक तबके की नीयत में रही हैं और ये अक्सर तब सबसे तीखे हुए जब केंद्र और राज्य में तकरीबन बिल्कुल उलट विचारधाराओं वाली सरकारें रहीं. केरल की वाम सरकार ने राज्यपाल खान की मौजूदा कार्रवाइयों को केरल में आरएसएस का हिंदू-बहुसंख्यकवादी एजेंडा थोपने की राजभवन की कोशिश करार दिया तो बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शिक्षा क्षेत्र के कथित राजनीतिकरण और नाकाबिल उम्मीदवारों को वीसी बनाने के

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को उनके विवेकाधिकार की सीमाएं बार-बार याद दिलाई हैं...उपकुलपतियों की नियुक्ति राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच विवाद की मुख्य जड़ बनकर उभरी है

लेकर ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल सरकार को खुलेआम फटकार लगाई थी.

उपकुलपति पर किसकी हुकूमत?

विडंबना यह है कि राज्यपालों को कुलाधिपति का पद और कुछ सांविधिक अधिकार देने के पीछे मूल इरादा विश्वविद्यालयों को राजनैतिक प्रभाव से अछूता रखना था. उपकुलपतियों की नियुक्ति में यूजीसी के नियम मानक दिशानिर्देश हैं. यूजीसी के नियमों के मुताबिक ''कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति'', जो राज्यों में ज्यादातर राज्यपाल ही होते हैं, खोज-सह-चयन समितियों की तरफ से सिफारिश किए गए नामों की सूची में से वीसी की नियुक्ति करेंगे. मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव होने पर राज्य सरकारों को यूजीसी के नियम-कायदों का पालन करना होगा, जो केंद्रीय कानून है. हाल के वक्त में खान सहित कई राज्यपालों ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन के आधार पर उपकुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए. जवाब में राज्य सरकारों ने राज्यपाल से कुलाधिपति की भूमिका वापस लेकर उलट हमला करने की कोशिश की. जून में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल को राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाते हुए और यह भूमिका उनकी बजाए मुख्यमंत्री को सौंपते हुए विधेयक पारित किया. विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है, उसी तरह जैसे तमिलनाडु विधानसभा में पारित ऐसा ही विधेयक भी कर रहा है. पंजाब सरकार भी इसी रास्ते पर चलते हुए राज्यपाल के बजाए मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने पर विचार कर रही है.

संविधान के अनुच्छेद 200 के मुताबिक, विधानसभा में पारित हर विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है. राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं—मंजूरी दे, मंजूरी रोक ले, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दे, अथवा पूरे विधेयक या उसके कुछ पहलुओं पर दोबारा विचार करने के लिए कहते हुए विधायिका को लौटा दे. राज्यपाल विधेयक में संशोधन भी सुझा सकता है. विधानसभा अगर विधेयक को उसी रूप में फिर पारित कर दे, तो राज्यपाल उसे नामंजूर नहीं कर सकता.

संविधान राज्यपाल को विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने का अधिकार देता है, ताकि पक्का किया जा सके कि राज्य का कानून संवैधानिक ढांचे के दायरे में है. राज्यपाल के ऐसे हस्तक्षेप बहुत विरले ही होने की उम्मीद की जाती है, पर शिक्षा से जुड़े मामलों को अक्सर ऐसी छानबीन से गुजरना पड़ा है. शिक्षा हालांकि समवर्ती सूची में है, जिसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं. केंद्रीय सूची की प्रविष्टि संख्या 66 का वास्ता उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण से है और यह उच्च शिक्षा के मामले में केंद्र को काफी अधिकार देती है.

राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल की तरफ से भेजे गए ऐसे संदर्भ का जवाब देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. कई राज्य सरकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल राज्यपाल की राजनैतिक विचारधारा के खिलाफ जाने वाले विधेयकों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया जाता है. चूंकि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इसलिए ज्यादातर वे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, हालांकि संविधान में सैद्धांतिक तौर पर ऐसा होने की परिकल्पना नहीं की गई थी. ऐसे विधेयकों को अटकाने का दूसरा तरीका उन पर कोई भी फैसला न लेना है. इस तरह न तो मंजूरी देकर और न ही विधानसभा को वापस भेजकर उसे विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद रद्द हो जाने दिया जाता है. संवैधानिक विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचारी कहते हैं, ''इस तरह कार्रवाई न करना गैरकानूनी है. संविधान राज्यपाल को चार विकल्प देता है. वे फैसला लटका नहीं सकते, क्योंकि यह उन चार विकल्पों में नहीं है.''

कितनी दूर जा सकते हैं राज्यपाल?

मंत्रियों को बर्खास्त करने की खान की हालिया धमकी से राज्यपाल के पद की भूमिका, शक्तियों और विवेकाधिकार पर ध्यान गया

है. संविधान का अनुच्छेद 154 कहता है कि सरकार की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि कई राज्यपाल इस पाठ की शाब्दिक व्याख्या कर संविधान की मूल भावना को अनदेखा कर रहे हैं. मंत्रियों को बर्खास्त करने की खान की धमकी ऐसी ही व्याख्या पर आधारित है. आचारी कहते हैं, ''अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किए जाते हैं. इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना मंत्री को नहीं हटा सकता.''

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को उनके विवेकाधिकार की सीमाएं बार-बार याद दिलाई है. मसलन संविधान कहता है कि राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर विधानसभा का सत्र बुलाएंगे जो वे उपयुक्त समझें. इसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने मुख्यमंत्री से सलाह-मशविरा किए बिना विधानसभा का सत्र बुलाया तो शीर्ष अदालत ने उस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया. प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा, ''राज्यपाल मुख्यमंत्री की अगुआई वाली मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से ही सदन बुला सकते, सत्रावसान कर सकते या भंग कर सकते हैं. स्वयं अपनी इच्छा से नहीं.'' अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ''उसकी मंत्री परिषद की सलाह के विरुद्ध या उसके बिना कार्य करने का सामान्य विवेकाधीन अधिकार'' नहीं देता.

विजयन ने खान को उनके अधिकारों की सीमाएं याद दिलाई, तो पंजाब में उनके समकक्ष मान ने राज्यपाल पर उनकी सरकार के कामकाज में ''लगातार दखलअंदाजी करने'' का आरोप लगाया, जिसे राज्यपाल पुरोहित ने ''निराधार'' कहकर खारिज कर दिया. दरअसल, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने ''विवेकाधीन शक्तियों'' से संपन्न मनोनीत राज्यपाल के निष्पक्ष काम करने को लेकर शंकाएं जाहिर की थीं. उन्होंने अनुच्छेद 147 (अब 167) को लेकर भी संदेह व्यक्त किए थे, जो राज्यपाल को ''सरकार के मामलों के प्रशासन और कानून बनाने के प्रस्तावों'' के बारे में मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार देता है. बी.आर. आंबेडकर ने हालांकि राज्यपाल के पद को ''आलंकारिक'' बताते हुए उसके अधिकारों को ''सीमित'' और ''नाम मात्र के'' अधिकार कहा था. संविधान सभा में अपने एक मशहूर भाषण में संविधान के जनक ने कहा था कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो वह अकेले अपने बूते पूरा कर सके और उसके पास करने के लिए केवल कुछ निश्चित कर्तव्य हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार विधेयक को मंजूरी देने या रोकने या राष्ट्रपति को भेजने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने या विधानसभा का विश्वास खोने के बाद भी छोड़ने से इनकार कर रही सरकार को बर्खास्त करने सरीखे कुछ निश्चित क्षेत्रों तक सीमित हैं. यह बात सबसे पहले 1974 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने शमशेर सिंह मामले में कही. 1994 में एस.आर. बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से छूट हासिल नहीं है, आपातकाल लगाने का औचित्य केवल तभी है जब संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई हो, न कि प्रशासनिक मशीनरी.

सुधारों पर कोई काम नहीं

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधार तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), सरकारिया आयोग (1988) और एम.एम. पुंछी आयोग (2010) सरीखे बहुत-से आयोग बनाए. उनकी रिपोर्ट स्वतंत्र और व्यापक तंत्र के जरिए गैर-राजनैतिक राज्यपालों की नियुक्ति करने, नियुक्ति के बारे में संबंधित मुख्यमंत्री की सम्मति लेने और राज्यपालों को निश्चित और बढ़ाया न जा सकने वाला कार्यकाल देने की बात कहती हैं. राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में विवेकाधिकार के प्रयोग के तरीके को लेकर भी सिफारिशें की गई हैं. केंद्र की किसी भी सरकार ने अलबत्ता इनमें से किसी भी रिपोर्ट और सिफारिश को लागू करने का बीड़ा नहीं उठाया. दिलचस्प यह है कि 1980 के दशक में राज्यपाल के रूप में 'अपना आदमी' चुनने का केंद्र का एकाधिकार खत्म करने की गरज से भाजपा ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति विधानसभा की तरफ से तैयार सूची से की जानी चाहिए और नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद के पास होना चाहिए, केंद्र सरकार के पास नहीं.

संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल की भूमिका की कल्पना ऐसे पहरुए के रूप में की थी जो संघ और राज्यों के बीच अहम कड़ी का काम करे. खुद सरकार की तरह काम करने की बजाए राज्यपालों को यह पक्का करना चाहिए कि सरकार अच्छी तरह काम करे. ■

विवेकाधिकार की सीमाएं

राज्यपाल को दो किस्म के विवेकाधिकार हैं—संवैधानिक (जिनका संविधान में जिक्र है) और स्थितिजन्य (आकस्मिक राजनैतिक स्थिति से उत्पन्न). संविधान कहता है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''राज्यपाल के विवेकाधिकार के प्रयोग का दायरा बहुत सीमित है''

संवैधानिक विवेकाधिकार

- विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना
- राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्यायिक समीक्षा के अधीन है
- पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के कर्तव्यों का निर्वहन (अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में)
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों की तरफ से खनिज उत्खनन लाइसेंस की रॉयल्टी के रूप में स्वायत्त आदिवासी जिला परिषदों को देने योग्य धनराशि का निर्धारण
- राज्य प्रशासन और विधायी मामलों के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना

स्थितिजन्य विवेकाधिकार

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले या जब पदासीन मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो
- विधानसभा का विश्वास साबित न कर पाने पर मंत्रीपरिषद को बर्खास्त करना
- जब मंत्रीपरिषद अपना बहुमत गंवा बैठे, विधानसभा को भंग करना
- राज्यपाल को कुछ निश्चित कर्तव्य भी सौंपे गए हैं जो उसे राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार पूरे करने चाहिए. राज्यपाल को वैसे तो मुख्यमंत्री की अगुआई वाली मंत्रीपरिषद की सलाह से काम करना होता है, पर इस मामले में वह अपने विवेक से कार्य करता है

दोषियों को मिले

मोरबी हादसे में जिम्मेदारी तय करने का काम अभी चल रहा है, इसके दोषी कौन हैं और क्या उन्हें वाकई सजा मिल पाएगी?

सजा

जुमाना शाह

टूटकर मुड़ गया
गुजरात के मोरबी में पुल टूटने की दुर्घटना के बाद जारी बचाव का कार्य

फोटो: पीटीआइ

जश्न

जरात में दीवाली के उल्लास और आनंद का उस वक्त खौफनाक तरीके से अंत हुआ जब 30 अक्तूबर को मोरबी कस्बे में मच्छू नदी पर बना झूला पुल टूट गया. घटना में कम से कम 134 लोगों की जान गई और कई हताहत हुए. विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की संभावित घोषणा से ठीक पहले इस त्रासदी का समय, स्थान और संदर्भ सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बुरी खबर लेकर आया. उसकी दोनों मुख्य प्रतिद्वंद्वी—आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस—ने भले ही बचाव कार्य खत्म होने तक जुबानी जंग छेड़ने से परहेज किया हो, पर हादसे की तह में दबी इबारतें चीख-चीखकर बोल रही हैं. सत्ता विरोधी भावना वैसे भी राज्य में विपक्ष के अभियान की सबसे प्रमुख थीम है, उसके साथ अब इस त्रासदी से पैदा गुस्से और आक्रोश का इन अहम चुनावों पर अच्छा-खासा असर पड़ने की पूरी संभावना है.

लेकिन सबसे पहले यह भयानक हादसा कुछ मोर्चों पर आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की मांग करता है. पुल को मोरबी नगरपालिका ने बिना सुरक्षा ऑडिट के जनता के लिए खोल दिया. इतना ही नहीं इन आश्यकताओं का उल्लेख किए बगैर इसकी मरम्मत और रखरखाव का काम अजंता ब्रांड नाम से दीवार घड़ियां बनाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को दे दिया गया. मोरबी नगरपालिका के प्रमुख संदीपसिंह झाला ने बताया कि पुल उनकी अनुमति के बगैर खोल दिया गया. ओरेवा के चेयरमैन जयसुख पटेल के हाथों उद्घाटन के बाद और गिरने से पहले चार दिन तक इस पर आवाजाही होती रही. यह पता नहीं चल सका कि नगरपालिका के अफसरों ने सुरक्षा प्रमाणपत्र न होने की वजह से इसे बंद करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया.

हादसे में अभी तक नौ लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें ओरेवा से वेतन पाने वाले दो मैनेजर, दो टिकट क्लर्क के साथ दो ठेकेदार (पुल की मरम्मत

निराशा और शोक का एक पुल

मच्छू नदी पर बने इस 143 साल पुराने पुल की छह महीने से अधिक समय तक नवीनीकरण और मरम्मत की गई थी. उसके बाद इसे हादसे से महज चार दिन पहले लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया था. कभी इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाने वाले इस पुल के ढहने की आखिर क्या वजह है?

ग्राफिकः **नीलांजन दास** और **तन्मय चक्रवर्ती**
आलेखः **जुमाना शाह**

इतिहास

बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर सर रिचर्ड टेंपल ने 20 फरवरी, 1879 को इसका उद्घाटन किया था. इस झूलते पुल का निर्माण मोरबी रियासत के तत्कालीन शासक सर वाघजी ठाकोर के शासनकाल में हुआ था. मच्छू नदी के दोनों ओर दरबारगढ़ महल और नजरबाग महल को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था

3.5
लाख रु.
निर्माण की लागत

पांच प्रमुख चूकें

1. सुरक्षा ऑडिट के बगैर ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया
2. पुल पर लोगों की भीड़ नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं हुआ
3. पुल की मरम्मत के दायरे को लेकर अस्पष्टता है. पुलिस कहती है कि डेक पर मटेरियल ज्यादा लगाने से इसका वजन बढ़ गया लेकिन जंग लगे केबल नहीं बदले गए
4. मोरबी नगरपालिका का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं माना गया
5. लोग पूछ रहे हैं कि ओरेवा ग्रुप के चेयरमैन जयसुख पटेल और कंपनी के प्रबंधकों पर एफआइआर क्यों नहीं हुई

- प्रति व्यक्ति 17 रुपए की दर से तकरीबन 600 टिकट बेच दिए गए थे
- इसकी 125 लोगों की स्वीकृत क्षमता की बजाए 350-400 लोग पुल पर आ गए थे
- लकड़ी के मूल डेक यानी फर्श को बदलकर उसे चार परतों वाले एल्यूमीनियम के फर्श में बदल दिया गया था, जिससे पुल का वजन बढ़ गया था
- पुल के केबल यानी तारों को नहीं बदला गया था

पुल का डेक

संरचना

पुल का प्रकारः **सस्पेंशन या झूला पुल**

पुल का डेक लंबवत सस्पेंडर्स पर सस्पेंशन केबलों से नीचे लटका हुआ है. मुख्य केबल पुल के दोनों छोरों पर टावरों को जोड़ते हैं, और लंबवत सस्पेंडरों के साथ डेक का भार वहन करते हैं

1
करोड़ रु.
मरम्मत की लागत 2007 में

2
करोड़ रु.
मरम्मत और नवीनीकरण की लागत इस साल

रखरखाव और मरम्मत

- कम-से-कम एक दर्जन बार रखरखाव के लिए बंद किया गया
- इस पुल को 2001 के भूकंप में काफी अधिक नुक्सान पहुंचा था, जिसके बाद इसे दो साल तक मरम्मत के लिए बंद रखा गया था
- अजंता घड़ियां और ई-बाइक बनाने वाले ओरेवा ग्रुप को 2007 में इस पुल के रखरखाव का जिम्मा दिया गया था
- पुल के रखरखाव और संचालन के लिए ओरेवा ग्रुप ने 15 साल के अनुबंध पर दस्तखत किए
- मरम्मत और नवीनीकरण के लिए मार्च 2022 में पुल को बंद कर दिया गया
- पुल को 26 अक्तूबर को खोल दिया गया, जबकि अनुबंध में निर्दिष्ट था कि इसे मरम्मत कार्य के दौरान 8-12 महीनों तक बंद रखा जाना होगा

आखिर कैसे ढह गया पुल

- उपलब्ध विजुअल्स और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर, ऐसा लगता है कि दो में से एक सस्पेंशन केबल टूट गया जिससे डेक भी अचानक टूटकर गिर गया
- एक और संभावना यह है कि डेक के साथ लंबवत केबलों को सुरक्षित करने वाले जोड़ टूट गए, खासकर पुल के एक छोर पर, जिससे पुल का स्थिर हिस्सा लोगों के साथ नदी में गिर गया
- पुल पर ज्यादा भीड़ हो गई थी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पता चलता है कि इसकी 125 लोगों की क्षमता की बजाए पुल पर 350-400 लोग आ गए थे
- पुल पर चढ़े कुछ लोगों की ओर से इसे अत्यधिक हिलाया जाना भी एक अन्य संभावित कारण बताया जा रहा है जिसकी जांच की जरूरत है
- हालिया मरम्मतों के दौरान मूल लकड़ी के डेक को बदलकर उसे एल्यूमीनियम का बना दिया गया था, जिससे पुल का वजन बढ़ गया था, लेकिन केबलों को मजबूत नहीं किया गया था. इससे संयोजक तंत्र पर बहुत अधिक दबाव पड़ा

60 फुट ऊंचाई*
765 फुट लंबाई
4.5 फुट चौड़ाई

*जमीन से, निर्माण के समय

BHADOO SAHIB

नंदन दवे

लाशों की गिनती
मच्छू नदी से निकले शवों को ले जाते सुरक्षाकर्मी

भाजपा उम्मीद कर रही है कि राज्य में चुनाव होने तक घटना अहम मुद्दा नहीं रह जाएगी तो हादसा मतदाताओं के दिलो-दिमाग में बना रहे, यह पक्का करने में **कांग्रेस और आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगी**

के लिए जिम्मेदार) और दो सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं जिन्हें ओरेवा ने रखा था. इन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है. 2 नवंबर को अदालत में पेशी के दौरान ओरेवा में जयसुख पटेल के एक करीबी सहयोगी ने इसे ''दैवीय घटना'' बताया. खास बात यह है कि ओरेवा से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली नगरपालिका से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई.

फिर ओरेवा के प्रोमोटर और शीर्ष अफसरों का भी मामला है जिनमें से किसी का नाम एफआइआर में नहीं है. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात के मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्र में इस मुद्दे को उठाया है. पत्र में कहा गया है, ''एफआइआर में ओरेवा ग्रुप के मालिक का नाम नहीं है और उनके शीर्ष प्रबंधन से न तो किसी की गिरफ्तारी हुई और न पूछताछ, जबकि गार्ड और छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया है. लिहाजा घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है.''

ओरेवा मोरबी का प्रमुख कारोबारी घराना है और इसका राजनैतिक प्रभुत्व भी है. कुछ लोग संदेह जाहिर करते हैं कि एफआइआर से जयसुख का नाम बाहर रहने के पीछे उनके भाजपा के राज्यसभा सांसद परशोत्तम रूपाला से पारिवारिक संबंध भी हैं. नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब रूपाला वहां मंत्री थे. जयसुख की भतीजी की शादी रूपाला के परिवार में हुई है.

दरअसल, ओरेवा ने 143 साल पुराने इस सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत और देखरेख का काम ध्रांगध्रा की कंपनी देवप्रकाश सॉल्यूशंस को ठेके पर दे दिया था. मरम्मत का क्या काम होना है इस पर स्थिति अभी भी साफ नहीं है जिसके लिए पुल को 8-12 महीने बंद रहना था लेकिन इसे सात महीने बाद ही खोल दिया गया. स्थानीय पुलिस की आरंभिक जांच में यह तथ्य पता चला है कि ब्रिज के डेक पर अतिरिक्त सामग्री लगाई गई जिससे इसका वजन काफी बढ़ गया और इसी वजह से यह 30 अक्तूबर को भरभराकर गिर गया. स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट के बैगर इसे नहीं खोल जाना चाहिए था.

2 नवंबर को पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय अदालत को बताया कि सस्पेंशन ब्रिज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केबल होते हैं जिनमें जंग लगी हुई थी और इन्हें बदलना जरूरी था. जंग लगे केबल पर शायद ही कभी पेंट किया गया हो और शायद ये ज्यादा वजन के कारण टूट गए. इस तरह के पुलों पर वजन एक सीमा के भीतर ही रखा जाता है. एक टिकट 17 रुपए में बेचा गया जिस पर ओरेवा का लोगो तो है लेकिन सीरियल नंबर नहीं है जिससे पुल पर लोगों की संख्या की निगरानी करना मुश्किल हो गया. स्पष्ट तौर पर यहां भी जिम्मेदारी का परित्याग कर दिया गया.

दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए बनी पांच सदस्यीय जांच समिति को लेकर भी असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं. मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री रहे एक नेता का कहना है, ''सभी सदस्य सरकारी मुलाजिम हैं और उनसे सरकार की आलोचनात्मक रिपोर्ट मिलने की गुंजाइश नहीं है. साथ ही वे इस विषय के विशेषज्ञ भी नहीं हैं.''

आप के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव इसुदान गढ़वी ने कहा, ''जिला कलेक्टर ने पुल खोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, पर गांधीनगर (राज्य की राजधानी) से फोन आने के बाद खोल दिया गया.'' कांग्रेस और आप दोनों सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और राज्य प्रशासन की कथित कमियों की बखिया उधेड़ रही हैं. भाजपा नेताओं का कहना है कि हादसे से पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं होगा.

भगवा खेमे के नेताओं का कहना है कि इस त्रासदी का असर चुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर नहीं पड़ेगा. पार्टी प्रवक्ता यमल व्यास राजनैतिक तौर पर भाजपा के ''इस इलाके में बहुत मजबूत'' होने पर जोर देते हुए कहते हैं, ''हमें टिकाऊ असर की उम्मीद नहीं है. यह बहुत तकलीफदेह घटना थी और हमारी सरकार ने सबसे असाधारण बचाव कार्य किए. पहला पीड़ित 18 मिनट के भीतर अस्पताल में था.'' हालांकि एक पूर्व विधायक स्वीकार करते हैं कि नुक्सान हो सकता है. वे कहते हैं, ''जनता के मनोविज्ञान पर त्रासदी के असर को समझने के लिए हमने अपने कान जमीन से लगा रखे हैं.''

भगवा खेमा उम्मीद कर रहा है कि एक महीने बाद राज्य में चुनाव होने तक मोरबी की घटना अहम मुद्दा नहीं रह जाएगी, तो कांग्रेस और आप यह पक्का करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगी कि यह हादसा मतदाताओं के दिलो-दिमाग में बना रहे. ■

ये पादरी पंजाब के

ईसाई उपदेशकों को अपने धार्मिक असर के विस्तार और ईसाइयत के फैलाव के लिए पंजाब की सबसे शोषित-उपेक्षित जातियों में मिल गई माकूल और उर्वर जमीन

अनिलेश एस. महाजन और सुनील मेनन • सभी फोटोः बंदीप सिंह

रामजीत सिंह 64 वर्ष
फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च,
कोट मीत सिंह, अमृतसर

पादरीनामा

''सिख धर्म ने बताया कि भगवान है, बाइबल ने रास्ता दिखाया कि उन्हें पाऊं कैसे''

जट सिख रामजीत सिंह नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद शराब और अवसाद में डूब गए थे. ''ट्रेन के कटने को मैं घर से रेलवे ट्रैक की ओर निकला था. तभी चमकते चेहरे वाला एक आदमी (शायद यीशु) मिला और मुझे बेटियों का वास्ता देकर घर जाने को कहा. उसकी बात मानी और बुरी आदतें छोड़ने का फैसला किया.'' अब रामजीत फर्स्ट बैपटिस्ट चर्च का हिस्सा हैं. वे पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं. इससे उन्हें अपने ईसाई धर्म और एक सिख जैसी वेशभूषा के बीच कभी विरोधाभास महसूस नहीं हुआ. खुद में वे दोनों को पाते हैं: ''सिख धर्म ने मुझे सिखाया कि ईश्वर है, बाइबल मुझे सिखाती है कि उसे कैसे खोजा जाए.''

ग

ह पंजाब में संधि का समय है, ऐसा समय जब अलग-अलग तरह की सीमाओं पर चीजें एक-दूसरे से मिलती हैं और घुल-मिल जाती हैं, एक-दूसरे की गांठें खोलती हैं, दरारें भरती हैं और अपना सुख-दुख सुनाती हैं. हवा में सर्दियों की आमद के साथ बीतती शरद ऋतु की उमस घुलती जा रही है. नीचे एकड़ों में फैला हरा-भरा धान साफ किया जा रहा है, ताकि सुनहरी गेहुईं चादर दूर तक बिछाई जा सके. हल गहरे खोदते हैं, आदमी के जेहन में, तो एक और ही तरह की फसल उग आती है. धर्म भारत की चेतना में गुणसूत्रों की तरह पिरोया हुआ है. वह हकीकत पर राज करता है, वह सामाजिक आचार-व्यवहार को आकार देता है, वह आगे बढ़ाता है और दिशा दिखाता है, और उसी शिद्दत से वह पराया बनाता और दो-फाड़ कर देता है. यहां पंजाब की घुली-मिली धरती के इतिहास में कुछ अनोखा और सीमाएं तोड़ने वाला एहसास पैदा हो रहा है. दुनिया भर में पेंटेकॉस्टल मूवमेंट से प्रभावित करिश्माई ईसाइयत की एक लहर पंजाब में सैलाब सरीखी बन रही है और तमाम तरह की टकराहटों का एहसास जगा रही है. उस दायरे के भीतर पहुंच गए लोगों में उससे जुड़ाव और उम्मीद का गहरा एहसास है, तो उसे बाहर से देखने वालों में वह बेचैनी बढ़ा रही है. ये नई सरहदें हैं, जिनका पंजाब आदी नहीं है और नहीं जानता कि इसे कैसे संभाला जाए.

उस वक्त तक सब कुछ एकदम सामान्य दिखता है जब तक आप जालंधर के देसज शहरी माहौल से उसके एक छोर खंब्रा गांव की ओर रुख नहीं करते. रविवार को अंकुर नरूला मिनिस्ट्री पहुंचना दिल्ली के अक्षरधाम परिसर में जाने जैसा है; 65 एकड़ के इस परिसर का दायरा और भी बड़ा है. इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्षेत्र से मेल खाता है. महज 37 साल के, जालंधर में संगमरमर का व्यापार करने वाले एक हिंदू खत्री परिवार में

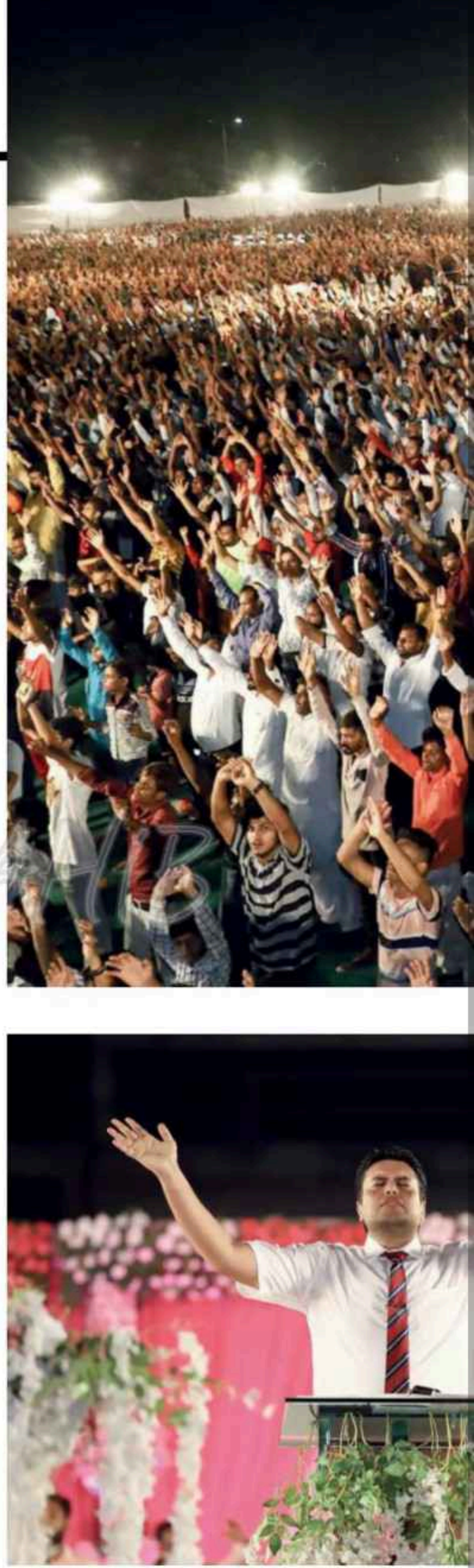

अंकुर योसेफ नरूला, 43 वर्ष
चर्च ऑफ साइन्स ऐंड वंडर्स,
अंबा, जालंधर

पादरीनामा

"हम पर होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए हम धरना नहीं, 'संवाद और चर्चा' का सहारा लेंगे"

जालंधर में एक हिंदू खत्री व्यवसायी परिवार में जन्मे नरूला दक्षिण अफ्रीकी पादरियों से प्रभावित थे. उनके वीडियो देखते थे. उनके मुताबिक, यीशु ने सपने में आकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा. उन्होंने 2008 में तीन अनुयायियों के साथ मिनिस्ट्री शुरू की. आज यह पंजाब का सबसे बड़ा चर्च है, जो दुनिया भर में 3,00,000 सदस्य होना का दावा करता है. इसकी रविवार की सभाओं में 10 से 15 हजार लोग आते हैं. उनके यूट्यूब चैनल के 12.3 लाख सब्सक्राइबर हैं. वे कहते हैं कि प्रवचनों के जरिए वे लोगों की तकलीफ दूर करते हैं. नरूला का दावा है कि वे गठिया से लेकर लकवा और कैंसर तक ठीक कर सकते हैं, यहां तक कि मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं. उन पर सिख समूहों ने हमला भी किया था लेकिन उनका कहना है कि उनकी कार्य समिति इसके लिए धरना नहीं, 'संवाद और चर्चा' का सहारा लेगी.

सुखपाल राजा, 44 वर्ष
द सुखविंदर राजा मिनिस्ट्रीज,
ददुआना, अमृतसर

BHADOO SAHIB

पादरीनामा

"एक चमत्कार ने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बदल दिया"

31 अगस्त के आखिरी हफ्ते में निहंग सिखों के एक समूह ने राजा की रविवार की धार्मिक सभा पर हमला किया. उन्हें लगा कि राजा और उनकी मिनिस्ट्री (ईसाइयों की धार्मिक सभा) लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रही थी और वे इस बात से नाराज थे. अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के निहंगों का समर्थन करने के बाद हमले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिखों का ध्यान खींचा. सांसी जनजाति के राजा दसेक साल पहले ईसाई धर्म अपनाने से पहले एक बेकरी में काम करते थे. उन्हें लकवा मार गया था और उनका दावा है कि प्रार्थना से उनका लकवा ठीक हो गया. राजा कहते हैं, "चमत्कार ने मेरी और परिवार की जिंदगी बदल दी." जट सिखों ने उनके परिवार को स्थानीय गुरुद्वारे में प्रवेश करने से कई बार रोका. "उन्हें हमारे मांसाहारी खाने पर ऐतराज था. अब कोई हम पर कुछ थोप नहीं सकता." उनकी धार्मिक सभा अभी बंद है. राजा को उम्मीद है कि वे एक दिन जमीन खरीदेंगे और सभाएं फिर से शुरू करेंगे.

जन्मे, नरूला का गोल चेहरा-मोहरा आम मैनेजमेंट पेशेवरों जैसा ही है. लेकिन वे जिस चर्च ऑफ साइन्स ऐंड वंडर्स के कर्ताधर्ता हैं, वह पंजाब के नए करिश्माई इदारों में सबसे बड़ा है. यह छोटे-मोटे साम्राज्य सरीखा है. पंजाब के नौ जिलों के अलावा बिहार और बंगाल के साथ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ग्रेटर लंदन के हैरो में भी उसके ठिकाने हैं. 2008 में ईसाइयत में दीक्षित होने के बाद वे करिश्माई उपदेशक बन गए. शुरू में उनके तीन शिष्य थे. अब उनकी मिनिस्ट्री दुनिया भर में 3,00,000 अनुयायियों का दावा करती है, जो उन्हें प्यार से 'पापा' बुलाते हैं. अलबत्ता, उन्हें 'एपोस्टल' या दैवीय प्रचारक कहलाना ही पसंद है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों से इस संख्या का जरा मिलान करें, जब पंजाब में ईसाइयों की कुल संख्या 3,48,000 थी. यही वजह है कि दूसरे धर्मों के प्रतिष्ठान क्यों बेचैन होने लगे हैं. संख्या में इजाफे का डर ही दरअसल उन अटकलों को हवा दे रहा है कि हाल के वर्षों में ईसाई धर्मांतरण में तेजी आई है.

नरूला की मिनिस्ट्री में रविवार को कम से कम 10,000-15,000 की भीड़ जुटती है. सैकड़ों मोटरसाइकिलें, कारें और किराए की पीली स्कूल बसें धान के खेतों को पार करके बाहर

पादरीनामा

''ईसाई नेताओं के साथ मेरे अनुभव ने मुझे बदलकर रख दिया''

इरप्रीत देओल, *42* **वर्ष**
द ओपन डोर चर्च ऐंड जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री, ओजेवाल, कपूरथला

पंजाब के दोआबा क्षेत्र के अधिकांश युवाओं की तरह, बीसेक की उम्र के देओल भी कनाडा जाने और वहीं बसने का सपना देख रहे थे. पर किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था. उन्हें वीजा ही नहीं मिल सका. देओल के पिता हरभजन सिंह पहले से ही एक प्रसिद्ध पादरी थे, जिन्होंने 1988 में एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी के प्रभाव में धर्म बदला था. जट सिख से ईसाई बने देओल को पिता का द ओपन डोर चर्च विरासत में मिला, जो अपने नाम के बावजूद पंजाब के सबसे पुराने पेंटेकॉस्टल चर्चों में से एक है. देओल कहते हैं, ''मेरे पिता धार्मिक व्यक्ति थे पर मैं वैसा नहीं था. उनके सहयोगियों के साथ मेरे अनुभव, मेरे पिता के प्रति उनके सम्मान और सबसे बढ़कर, ईसाई नेताओं के साथ मेरे अपने अनुभव ने मुझे बदल दिया.'' 2012 से ही वे धार्मिक उपदेशक बन गए हैं और अब एक एकड़ भूमि पर चर्च बनवा रहे हैं जो उनकी मिनिस्ट्री से सटा हुआ है. उनके रविवार के उपदेश और उपचार सत्र (हीलिंग सेशन) में सबसे अधिक भीड़ होती है; उनका दावा है कि उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं से कैंसर रोगियों को भी ठीक किया है. वर्तमान में, देओल पीसीपीसी (पेंटेकॉस्टल चर्च प्रबंधक कमेटी) का एक ढांचा तैयार करने में व्यस्त हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी और अब वे पेंटेकॉस्टल पादरियों को संगठित करने जा रहे हैं.

विशाल पार्किंग में पहुंची हैं. परिसर के मेन गेट के बाहर चिप्स, कोक, लाइम सोडा, बर्गर के स्टॉल हैं. कुछ खोमचे वाले पापड़ बेचने के लिए धक्कापेल मचाए हुए हैं. परिसर के भीतर चार बड़े शामियानों में अत्याधुनिक वीडियो स्क्रीन और स्पीकर लगे हैं, इनके बीच से रास्ता विशाल निर्माणाधीन चर्च भवन तक पहुंचता है. पूरा होने पर इसके एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन जाने का दावा है. उपासना शुरू हो चुकी है. नरूला बर्मिंघम से लाइव हैं, जहां वे ब्रिटेन में चर्च ऑफ साइन्स ऐंड वंडर्स की दूसरी शाखा का उद्घाटन करने गए हैं. सुरक्षाकर्मियों और सफेद-पहनावे में परिचारकों की एक कतार है. उन्हीं में से कुछ भारी जनरेटरों के बगल में तीन भाषाओं में बाइबल, नरूला की *माई बुक ऑफ प्रोफेसीज* और मिनिस्ट्री की पत्रिका के स्टॉलों पर हैं.

इन धार्मिक समागमों में ऐसे बड़े पादरी भी शामिल हैं जिनके लाखों अनुयायी और यूट्यूब फॉलोअर हैं. इनकी शाखाएं भी हैं ग्रामीण पादरी घर से ही धर्मोपदेश देते हैं

भदेस सुधारक

उसी रविवार की सुबह अजनाला से 100 किमी दूर का जरा रुख करते हैं. ग्रामीण पंजाब की सुस्त, शांत हवा. धूल की चादर ओढ़े गांव, तालाब में मड़िया लेती भैंसें और देहात को दोफाड़ करती, नहर के साथ मीलों चलती पक्की सड़क, ताजा कटे धान और पॉपुलर के पेड़ों के झुरमुट. सेहंसरा कलां गांव किसी शहरी मध्यवर्गीय मोहल्ले जैसा ही दिखता है: चमचमाता सफेद गुरुद्वारा और चौड़े खड़ंजों के दोनों तरफ शानदार घर, जिनकी बालकनियां शीशे और लकड़ी के काम से सजी हैं. हालांकि, थोड़ा अंदर घुसिए तो गलियां आम गांवों जैसी ही संकरी हो जाती हैं.

एक लंबा, सांवला आदमी बाइक पर जाता दिखता है. सफेद कमीज, भूरी पैंट, करीने से संवारी दाढ़ी और आकर्षक मुस्कान. कद-काठी से वह कोई पुलिसवाला और पोशाक से रविवार की ड्यूटी पर किसी पादरी-सा लगता है. दरअसल, गुरनाम सिंह दोनों हैं: एक ही काया में समाई दो विरोधी शख्सियत (देखें: ''मैं धर्मांतरण नहीं कराता''). रास्ता एक और गुरुद्वारे के सामने पीपल की छांव में एक चौपाल तक जाता है. सपाट-सी छत पर दो लाउडस्पीकर लगे हैं, टूटी-फूटी दीवार से लगी छोटी-सी किराने की दुकान है. बगल से एक गली उतरती है, जिसकी दाहिनी ओर चारदीवारी के भीतर छोटा-सा सफेद घर है. फाइबर ग्लास के दरवाजे. एक हुंडई इयॉन शान से खड़ी है. उसकी जालीदार छत पर लगा क्रॉस चौपाल से लगभग नहीं दिखता. तभी हालालुइया (गॉड की प्रार्थना) गूंज उठता है.

अंदर धीरे-धीरे उपासना गति पकड़ती है. हॉल छोटा-सा है जिसका प्लास्टर यहां-वहां से उखड़ा हुआ है. गुलाबी फीतों से सजे छोटे-से मंच पर एक युवक कीबोर्ड पर आसान बोल वाले गीत के जरिए मोक्ष की तस्वीर बयान करता है. एक तरफ दर्जन भर महिलाएं बैठी हैं; दूसरी तरफ कुछ पुरुष किसानों जैसी पोशाक और हर मौसम के थपेड़े खाए चेहरे के साथ बैठे हैं. उन्हें पता है, कब ताली बजाकर सुर ऊंचा कर देना है, और कब धीमा. ऐसा लगता है, जैसे कोई कव्वाली हो रही है. युवक के सुर में सुर मिलाकर एक महिला गाती है. हालालुइया किसी देहाती कोरस में बदल जाता है, ठीक ऊंची सुरीली आवाज में जैसे जागरण गाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही. पादरी वहीं बैठा, ताली बजाता, टहलता, सब पर नजर रखता है. दीवारों पर लगे पोस्टर में वह दिखता है. एक में वह नवविवाहितों को आशीर्वाद देता पगड़ी पहने पुलिसवाला है. दूसरे में वह सलवार कमीज में दो गोरी मेमों के साथ, बिना पगड़ी के पादरी की पोशाक में दिखता है: यह है 'बेथेल मसीह सत्संग.'

धर्म का प्रचार

मिलिए पंजाब के इन नए पादरियों से. इनमें करीब दर्जन भर बड़े नाम हैं: अमृत संधू, कंचन मित्तल, रमन हंस, गुरनाम सिंह खेड़ा, हरजीत सिंह, सुखपाल राणा, फारिस मसीह. इनके अनुयाइयों की

मनोहर सिंह, 56 वर्ष
द मनोहर सिंह मिनिस्ट्रीज,
नारायणगढ़, अमृतसर

पादरीनामा

"मेरे पास साधन-सुविधाएं भले ही कम हों लेकिन मैं बड़े सुकून में हूं"

जब किसी को पता चलता है कि मनोहर सिंह ईसाई हैं तो उस व्यक्ति का पहला सवाल उनके रूप-रंग को लेकर होता है. कपड़े के व्यापारी रहे मनोहर ने ईसाई होने के बावजूद सिख पगड़ी और लंबी दाढ़ी बरकरार रखी. वे कहते हैं, "लोग जब मेरे पहनावे के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह मेरी तहजीब और परवरिश का हिस्सा है. ईसाई नबी भी अपनी-अपनी संस्कृतियों की पगड़ी पहनते थे." लबाना व्यापारी समुदाय के मनोहर ने अपनी किशोरवय बेटी की मृत्यु के बाद ईसाई धर्म अपना लिया. वे एक हादसे में अपने बेटे को गंवाने के कारण पहले से ही तनाव में थे. वे याद करते हैं, "कुछ पादरी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बड़ी मानसिक शांति दी. इसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया. अब भले ही मेरा घर बहुत छोटा है, संसाधन कम हैं और शायद मेरे पास सुख-सुविधाओं के साधन बहुत कम हैं लेकिन मैं हूं बड़े सुकून में."

बड़ी तादाद है. पंजाब में इनकी कई शाखाएं हैं और यूट्यूब पर इनके लाखों फॉलोअर हैं. इनमें हर तबके के लोग हैं: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, नौकरशाह, कारोबारी और जमींदार जिन्होंने या तो अपना पेशा छोड़ दिया है या साथ में रविवार को प्रचारक की भूमिका भी निभाते हैं. खंब्रा से कुछ मील दूर, कपूरथला जिले के गांव खोजेवाल में ओपन डोर चर्च अपनी पूर्वी यूरोपीय प्रोटेस्टेंट वास्तुकला से ध्यान खींचता है. यहां के आध्यात्मिक गुरु हरप्रीत देओल जट्ट सिख हैं, जो मेहमानों को चाय के साथ उबले अंडे पेश करते हैं (''तुस्सी अंडे खाओ''). बटाला के हरपुरा गांव के सर्जन-पादरी गुरनाम सिंह खेड़ा भी जट्ट सिख हैं. पटियाला के बनूर में चर्च ऑफ पीस के मित्तल बनिया हैं. और चमकौर साहिब के रमन हंस मजहबी सिख हैं. इनमें से कई निजी सुरक्षा गार्ड भी रखते हैं. देओल के कार्यालय में बड़े-बड़े बाउंसर और एक फिंगरप्रिंट युक्त सुरक्षा लॉक है.

पादरियों की शरण में आने वाले ज्यादातर लोग पंजाब के नौ सर्वाधिक सताए गए समुदायों में से हैं: मजहबी सिख-वाल्मीकि, सांसी, राय सिख, बावरिया, बाजीगर, नट आदि

इस कड़ी के दूसरे छोर पर गांव के पादरी हैं, साधारण आम आदमी. रविवार की प्रेयर अक्सर उनके अपने घर में ही आयोजित की जाती हैं. सेहंसरा के गुरनाम सिंह पंजाब पुलिस में एएसआइ हैं, अमृतसर में नारायणगढ़ के मनोहर सिंह छोटे कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे, पादरी गजान सिंह अटारी में खेत मजदूर थे, और दलबीर मसीह वेरका में छोटे-मोटे दर्जी थे. ये सभी पंजाब के सांस्कृतिक प्रतीकों में रचे-बसे हैं. जैसे, पगड़ी, लंगर (वे इसे जीसस दा लंगर कहते हैं), टप्पा गीत, गिद्दा नृत्य क्योंकि यह सब उनका अपना है. इसलिए उनके सत्संग आपको अलग न दिखकर उसी सिलसिले की कड़ी लगते हैं. इन्हीं गहरे राग-रंगों पर पादरी की शब्दावली चढ़ा दी जाती है, जो अमूमन देहरादून में न्यू थियोलॉजी कॉलेज या केरल में इंडियन बाइबल कॉलेज और सेमिनरी में प्रशिक्षण से हासिल होती है, लेकिन बोली पूरी तरह से स्थानीय. तभी दशमांश दान यहां दसवंड बन जाता है.

किसी पादरी के चमत्कार के दावे इस पर भी निर्भर हैं कि वह कितना नाटकीय है. और चमत्कारों से कुछ भी अछूता नहीं: भूत उतारना, कैंसर, जोड़ों का दर्द, बांझपन तक सबका इलाज, नशे की लत से लेकर नौकरी, वैवाहिक रिश्तों और वीजा तक एक भाव से मदद. कुछ ने तो मुर्दों को जिला देने का भी दावा किया है. हालांकि, जालंधर के ताजपुर गांव में रंगीनमिजाज विवादास्पद हरियाणवी जाट बजिंदर सिंह के चर्च ऑफ ग्लोरी ऐंड विजडम में चार वर्षीय कैंसर रोगी तनीषा की मृत्यु हो गई पर उपचार में आस्था बेरोकटोक चलती रही. देओल की सुनिए, ''लोग इसकी सचाई पर सवाल उठाते हैं पर चमत्कार संभव हैं और आस्था के लिए अहम.'' चमत्कार का तत्व सभी धर्मों में समान है. सूफी दरगाह, वैदिक यज्ञ, हरमंदिर साहिब के परिक्रमा पथ पर दुख भंजनी बेरी का पेड़, सभी चमत्कार के विचार पर आधारित हैं. और यह तर्क देना मुश्किल है कि आधुनिक भक्त वास्तव में इसमें विश्वास नहीं करते. तो फिर क्या चीज है जो करिश्माई आस्थावानों को इनसे अलग करती है? पंजाब में पेंटेकॉस्टल मूवमेंट डेरा प्रमुखों की तरह विश्वास करता है कि विश्वास महज पूजा-पाठ के बजाए अनुभव केंद्रित होना चाहिए. कोई भी विश्वासी अपने भगवान की मौजूदगी का सीधा अनुभव कर सके. यही इसका मुख्य आकर्षण है.

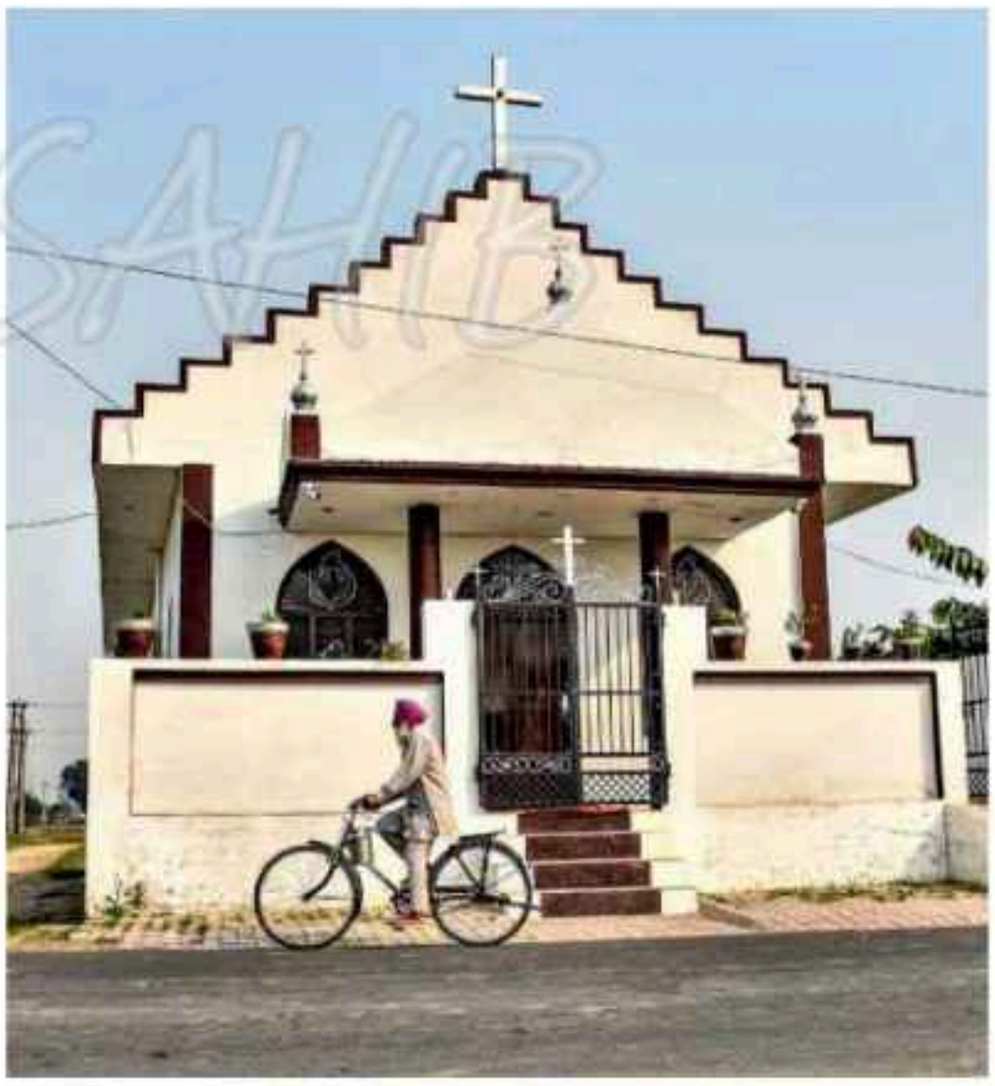

इसके अलावा, 'इलाज' कहीं अधिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक रूपक हो सकता है. यहां के अधिकांश अनुयायी पंजाब के नौ सबसे शोषित दलित/आदिवासी समुदायों से आते हैं, जिन्हें समृद्धि के दायरे से बाहर रखा गया है: मजहबी सिख-वाल्मीकि, सांसी, राय सिख, बावरिया, बाजीगर, बराड़, बंगला, गढीले और नट. एक नजरिया इन दिनों धर्मांतरण को 'अवैध' मानता है. लेकिन जिंदगी में बेहतर अवसरों की चाहत,

जाति के दंश से बचाव और अपने लिए एक समुदाय की भावना रखने में गलत या नाजायज क्या है भला? 2018 में यीशु की रोशनी में आने का दावा करने वाले अमृतसर के नारायणगढ़ के हरिंदर सिंह कहते हैं, ''मेरे बच्चे अब अच्छे स्कूलों में जा सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं. पादरी एक मिल में नौकरी दिला रहे हैं. मुझे ग्रंथी साहब से इतना स्नेह कभी नहीं मिला.'' भाजपा समर्थित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से माझा बेल्ट में सिख परिवारों के 'धर्मांतरण' का मुकाबला करने भेजे गए कार्यकर्ता मंजीत सिंह भोमा भी मानते हैं, ''अगर ये ईसाई समूह बच्चों को शिक्षा, किताबें या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच मुहैया करते हैं तो एसजीपीसी जैसे सिख संस्थानों को

चर्च का फैलता साम्राज्य

1. अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का बन रहा चर्च

2. अमृतसर के गुरु की वडाली में बना एक शानदार चर्च

3. अमृतसर के पास घुमावदार सीढ़ियों वाला एक चर्च

4. बटाला के बाहरी इलाके में बनाया गया एक चर्च

5. अमृतसर के नांगल दयाल सिंह गांव का एक चर्च

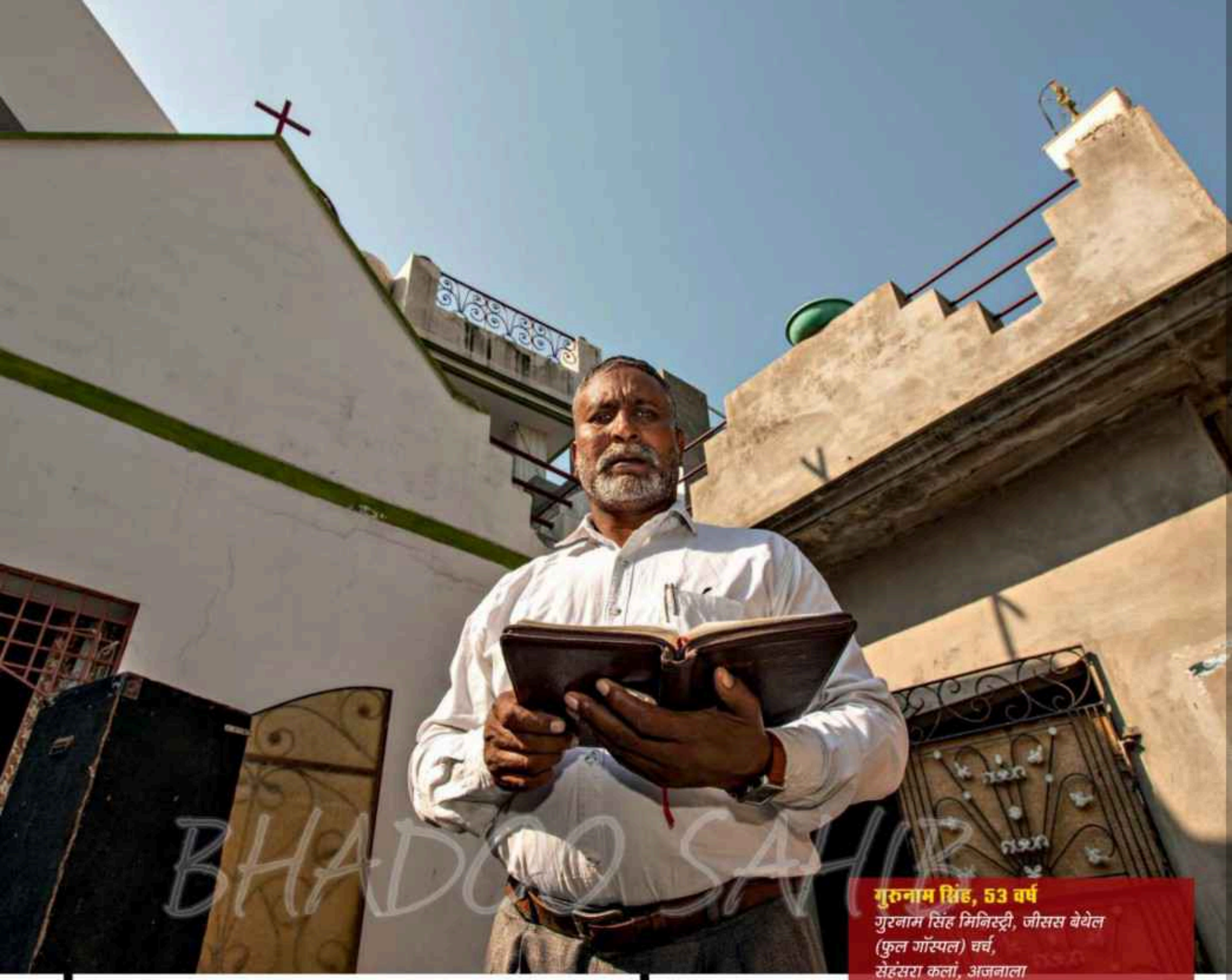

गुरुनाम सिंह, 53 वर्ष
गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री, जीसस बेथेल (फुल गॉस्पल) चर्च,
सेहंसरा कलां, अजनाला

पादरीनामा

"मैं लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराता, सिर्फ बाइबल का प्रचार करता हूं"

■

पंजाब पुलिस में एएसआइ गुरुनाम सिंह 1998 में परिवार से अलग होकर ईसाई बन गए. वे बताते हैं, "पत्नी बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी, तो परिवार चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं. मुझे यह मंजूर न था. मैं अमृतसर चला गया, जहां कुछ पादरियों के संपर्क में आया. उनकी दुआओं से अब मेरे तीन बच्चे हैं." मजहबी सिख गुरुनाम सिंह ड्यूटी के समय पगड़ी पहनते हैं और घर लौटने पर बाइबल का प्रचार करते हैं. उन्होंने घर के पिछले हिस्से को चर्च में बदल दिया है, जहां रविवार के उपदेश के दौरान करीब 50 लोग जुटते हैं. वे कहते हैं, "मैं धर्मांतरण नहीं करता, सिर्फ बाइबल का प्रचार करता हूं."

आत्ममंथन करना होगा कि इसमें गलत क्या है. जो लोग पाला बदल चुके हैं, उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल है."

पर इतना तो है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के इस भूत ने सभी पक्षों को हिलाकर रख दिया है. नव-ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाली ये तमाम मिनिस्ट्री पंजाब के 23 जिलों में फैली हुई हैं. माझा और दोआबा बेल्ट के अलावा मालवा में फिरोजपुर और फाजिल्का के सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रियता है. कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं पर एक अनुमान के मुताबिक पादरियों की कुल संख्या 65,000 है.

कैथोलिक प्रतिष्ठान जैसे मुख्यधारा के संगठन भी इस नए घटनाक्रम से हैरत में हैं क्योंकि पेंटेकोस्टलवाद से उनके अनुयायी भी छिटक रहे हैं. क्या वे सभी धर्मांतरण कर रहे हैं या केवल एक और पूजा स्थल पर सुकून तलाश रहे हैं जैसा कि भारतीय अपनी उदार धार्मिकता में करते हैं? शायद दोनों. अधिकांश पादरियों ने *इंडिया टुडे* से दावा किया कि वे धर्मांतरण नहीं कराते, केवल इलाज करते हैं-और लोगों को "दर्दनाक सच्चाइयों से बाहर निकलने" में मदद करते हैं. लेकिन यहां तौबा, पश्चाताप, और बप्तिस्मा की रस्म कराई

सामूहिक उपासना
गुरुदासपुर, पठानकोट और अमृतसर के पादरी फतेहगढ़ चूड़ियां में सैमुएल मसीह मिनिस्ट्री की सालाना कॉन्फ्रेंस में

जाती है. और पंजाब की 2.96 करोड़ आबादी के महज छोटे हिस्से में ही सही, इससे सहमत होने वालों की तादाद बढ़ रही है.

किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप जीने की आजादी देने वाले भारतीय संविधान में धर्मांतरण एक कानूनी अधिकार है. हालांकि, हाल के वर्षों में जबरन धर्मांतरण के आरोपों के बीच अलग-अलग राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की बाढ़ आ गई है. इनमें से कई को अदालत में चुनौती दी गई है क्योंकि इनमें 'प्रलोभन' की परिभाषा कुछ ज्यादा ही विस्तृत है. सिख धर्म खुद भी धर्मांतरण करवाता है और सैद्धांतिक तौर पर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एच.एस. धामी इस धार्मिक घटनाक्रम को ज्यादा तवज्जो नहीं देते. वे कहते हैं, ''लोग जिंदगी की समस्याओं के हल के लिए पादरियों के पास जाते हैं. देर-सबेर उन्हें सच्चाई पता चलेगी और वे मूल धर्म में लौट आएंगे.'' हालांकि, कहीं न कहीं चिंता साफ दिखने लगी है. एसजीपीसी ने 'घर घर अंदर धर्मसाल' जैसे जवाबी अभियान शुरू किए हैं, जहां स्वयंसेवक सिख धर्म का प्रचार करने घर-घर जाते हैं. 5 सितंबर को आनंदपुर साहिब में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय से धर्मांतरण पर अपने रवैये को लेकर पुनर्विचार करने को कहकर हड़कंप मचा दिया. पर इस रवैए के बावजूद पंजाब में लोभ-लालच से धर्मांतरण के संकेत आपको शायद ही कहीं मिलें. जैसे-जैसे कृपा प्राप्त हो रही है, लोग स्वेच्छा से उधर झुक रहे हैं.

लेकिन अब पानी नाक तक आ गया दिखता है. 29 अगस्त को निहंगों के एक समूह ने अमृतसर के दादुआना गांव में एक पेंटेकोस्टल चर्च में ''जबरन धर्मांतरण'' का आरोप लगाते हुए एक कार्यक्रम में अड़ंगा लगाया. दो दिन बाद चार नकाबपोशों ने तरनतारन के ठक्करपुरा गांव में एक कैथोलिक चर्च पर हमला किया, गार्ड को पकड़ा और मूर्तियों को तोड़ दिया. कैथोलिक प्रतिष्ठान ने शुरू में विरोध प्रदर्शन किया पर बाद में ''छोटी-मोटी छिनैती'' की घटना बताकर इसे रफा-दफा करने की कोशिश की. और 8 अक्तूबर को एक नया पहलू जुड़ा जब दुबई से लौटे, 'दूसरे भिंडरावाले' अमृतपाल सिंह ने रोडे गांव में अपने सम्मान के दौरान कहा कि ''जिन्होंने भी बेअदबी की, उन्हें न पुलिस को सौंपा जाएगा और न अदालतों में भेजा जाएगा. उन्हें हम सजा देंगे.''

प्रतिक्रिया से निबटने की युक्ति

ईसाई कार्यकर्ताओं ने 18 अक्तूबर को विरोध प्रदर्शन किया, पर कुल मिलाकर वे डर गए हैं. *इंडिया टुडे* की टीम जिन पादरियों से मिली, उनमें से कई तस्वीर खिंचवाने से कतरा रहे थे. नरूला ने तो मिलने से भी इनकार कर दिया, हालांकि वे धर्मोपदेशों के जरिए सिख धड़ों के लगाए आरोपों का जवाब देते हैं. इस उठापटक ने पादरियों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया. पिछले नवंबर में देओल ने पेंटेकोस्टल चर्च प्रबंधक कमेटी (पीसीपीसी) का गठन किया. उनके मुताबिक, अब 1,000 से ज्यादा पादरी पीसीपीसी के तहत पंजीकृत हैं. हालांकि अब राजनैतिक नुमाइंदगी की जरूरत महसूस की जा रही है और नरूला सरीखे बड़े नाम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्थानीय निकायों और पंचायतों में ईसाई सदस्य तो हैं पर पंजाब में ईसाई विधायक या सांसद नहीं हैं.

पंजाब के लिए ईसाई धर्म बेशक अजनबी नहीं है. 19वीं सदी के मध्य में इसका आगमन अनजाने में ही यहां के धार्मिक और सामाजिक जीवन की निर्णायक घटना बन गया. आर्य समाज की स्थापना 1875 में साफ तौर पर हिंदू धर्म के लिए उभर रहे कथित खतरों का प्रतिकार करने के लिए ही की गई थी—दयानंद सरस्वती यूरोपीय मिशनरियों की तरफ से की जा रही हिंदू धर्म की भर्त्सनाओं से आहत थे. मगर इसने खुद ही ब्रह्म समाज के ईसाई रंगत में ढले सुधारवाद को अपना लिया था. जाति की ग्रंथियों से मुक्त दयानंद आंग्ल-वैदिक स्कूल और कॉलेज स्पष्ट रूप से ईसाई संस्थाओं के मॉडल पर बनाए गए (बाद में आरएसएस ने भी यही मॉडल अपनाया). फिर धर्मांतरित लोगों को वापस लाने के लिए चलाए गए आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन ने भी वही

पादरीनामा

''मैंने चमत्कार देखे हैं, खुद भी कुछ चमत्कार किए हैं''

गुरनाम सिंह खेड़ा, 52 वर्ष
होली जीसस फायर चर्च और गुरनाम खेरा मिनिस्ट्रीज, हरपुरा, गुरदासपुर

दशकों से गुरनाम सिंह को गुरदासपुर क्षेत्र में दो चीजों के लिए जाना जाता था: पहला इलाके के एक प्रमुख चिकित्सक के रूप में और दूसरा जसवंत सिंह खेड़ा के छोटे भाई के रूप में जो खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़ा था और आतंकवादी वासन सिंह जफरवाल का करीबी सहयोगी था. जसवंत को 2006 में जब एक स्थानीय पादरी ने ईश्वर की 'प्राप्ति' का रास्ता बताया तो उसने ईसाई धर्म अपना लिया. एक साल बाद गुरनाम और उनके परिवार ने भी ईसाई धर्म की शरण ली. गुरनाम कहते हैं, ''मैंने चमत्कार देखे हैं, कुछ चमत्कार तो मैंने भी किए हैं.'' लेकिन जब वे धर्मोपदेश देते हैं, तब भी अपने सिर पर पगड़ी बांधे रखते हैं. वे कहते हैं, ''हाल ही में कुछ सिख संगठनों ने पुलिस से शिकायत की. मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपनी पगड़ी हटा दूंगा अगर यह संविधान के खिलाफ है या अवैध है. लेकिन इसे मैं सिर्फ इसलिए तो बिल्कुल नहीं हटाने वाला क्योंकि किसी सिख संगठन को इससे ऐतराज है.''

गुरनाम का तीन साल पहले समुदाय के साथ एक और टकराव उस वक्त हुआ था जब उनके पिता का अंतिम संस्कार सिखों के लिए बने श्मशान में नहीं करने दिया गया था और पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के दखल के बाद उन्हें एक ईसाई कब्रिस्तान में लेकर जाना पड़ा था.

महत्वाकांक्षा पाल ली जिसकी वह आलोचना करता था और इस कदर अपना ली कि वह विधि-विधान से पंजाबी धर्म—सिखी—के लिए खतरा बन गया. और इस सिख धर्म ने खुद को परिमार्जित करने वाले आंदोलन के जरिए इसका जवाब सिंह सभा के रूप में दिया, जिसने खालसा को ब्राह्मणवादी रवैए से मुक्त किया. इसने इस दावे को भी धता बताया कि सिख धर्म व्यापक हिंदू धर्म का ही हिस्सा है. उसने इसे स्वायत्त धर्म के रूप में इसकी चौहद्दी बनाई और उस आधुनिक सिख धर्म को जन्म दिया जिसे आज हम जानते हैं.

इसका दूसरा गहरा असर जाति प्रथा पर पड़ा. 1873 में सिर पर मैला ढोने वाली जाति—जिसे अब वाल्मीकि (हिंदुओं में) और मजहबी सिख की उपाधि दी गई है—के ''एक लंगड़े, काले आदमी'' दित्त सिंह ने सियालकोट में बपतिस्मा करवाकर पंजाब में ईसाइयत में धर्मांतरण की पहली लहर चलाई. उनकी जाति के लोग स्वप्रेरणा से इतनी बड़ी तादाद में उनके पीछे चल पड़े कि चर्च भी इन सबॉल्टर्न अनुयायियों से भौचक रह गया. पर महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह (जो बाद में फिर अपने धर्म में लौट आए) या कपूरथला के 'राजा सर' हरनाम सिंह सरीखी शख्सियतों के धर्मांतरण ने खासी खलबली मचाई थी.

आज के पंजाब में दलित कुल 31.9 फीसद हैं, जो किसी भी भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा अनुपात है. और पहले सिर पर मैला ढोती रही जाति 13.5 फीसद (मजहबी सिख 10 फीसद, वाल्मीकि 3.5 फीसद) हैं. सबसे ज्यादा लांछित जाति होने के नाते सिर पर मैला ढोने वाली जातियां पहली अर्धशती के दौरान धर्मांतरित होने वालों में सबसे आगे थीं. कारण समझना मुश्किल नहीं: शुद्ध और सरल मुक्ति. यह सदियों से चले आ रहे अपमान और शोषण की बेड़ियों से खुद को मुक्त करने का तरीका था. समाजशास्त्री मार्क जुरगेंसमायर ने 1982 की अपनी किताब *रिलीजन ऐज सोशल विजन* में लिखा था, ''पंजाब की ईसाइयत वस्तुत: अछूतों के उत्थान का आंदोलन बन गई, जो शायद आधुनिक इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन था.'' पहले-पहल धर्मांतरित लोग नए इलाकों में बस गए, खासकर जालंधर छावनी के आसपास तकरीबन पूरी तरह ईसाई गांवों में.

अविभाजित पंजाब की ईसाई आबादी 1870 में कुछ हजार से बढ़कर 1930 में पांच लाख हो गई. फिर यह लहर शांत पड़ गई. बंटवारे ने उनमें से बड़े हिस्से को रैडक्लिफ रेखा के दूसरी ओर रख दिया. फिर दशकों तक एक तरह से शांत मौजूदगी कायम रही और पुराने चर्च, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल सरीखे समाज उपयोगी उपक्रम खोलते-चलाते हुए वे शहर के फलक पर काम करने लगे. 2003 में तब के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने सिख प्रतिष्ठान, कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट के बीच एक समझौता करवाया: यही कि धर्मांतरण वैसे धीमी गति से हो रहे हैं पर इन्हें भी बंद करवा दिया जाए. ईसाई समुदाय अब भी

सवाल आस्था का
हरप्रीत देओल मिनिस्ट्री में एक पादरी प्रार्थना के जरिए एक बच्चे का उपचार करते हुए

छोटा ही है. 2011 की जनगणना में पंजाब की आबादी में ये महज 1.26 फीसद जबकि सिख (57.7 फीसद) और हिंदू (38.5 फीसद) मिलकर 96 फीसद हैं.

दरअसल चीजें 2000 के दशक में तमिल ईसाई धर्मप्रचारक दिनकरण के आने के साथ बदलनी शुरू हुईं. उनका करिश्माई टूलकिट अमेरिकी टीवी इवेंजेलिस्ट के सांचे में ढला था. उनके बाद उनके साथी रहे नरूला सरीखे दूसरे लोगों ने पेंटेकोस्टल आध्यात्मिकता का पूरा गुलदस्ता सजा दिया—संगीत और नृत्य के जरिए परमेश्वर के साथ समागम, परमानंद की अनुभूति, धार्मिक चिकित्सा के चमत्कारिक कृत्य. पंजाब पहले से ही कई तरह के सदमों में डूबा रहा था—सालों का उग्रवाद, खेती का संकट, नशे से डूबी युवा पीढ़ी. ऐसे में 'उम्मीद दिखाते पादरियों' के लिए यह उर्वर जमीन बना.

धर्मों की लोहभट्ठी

लेकिन हकीकत में पंजाब धर्मों, पंथों और प्रतिस्पर्धी धर्म प्रचार के लिहाज से एक तपती हांडी बना रहा. 1891 की जनगणना तक 'अछूत' जातियों को हिंदुओं में नहीं गिना जाता था. दरअसल सिर पर मैला ढोने वालों का अपना धर्म था—बाला शाही पंथ, जो 1884 में दर्ज रिचर्ड टेंपल के शब्दों में ''न हिंदू, न मुसलमान, बल्कि प्रीस्टहुड (पुरोहिताई) और अपने आप में अनोखे अनुष्ठान वाला'' था. आर्य समाज ने बाद में बाला शाह को वाल्मीकि की रामायण से जोड़कर इसका हिंदूकरण कर दिया.

सिख धर्म की बाहरी परिधि वाले निरंकारी और नामधारी जीते-जागते गुरुओं में विश्वास करते हैं, तो राधास्वामी और डेरा सच्चा सौदा सरीखी उनकी दूर-दराज की शाखाएं भी. डेरा आंदोलन, जो हिंदू, सिख और सूफी इस्लाम का एक मिला-जुला आध्यात्मिक रूप पेश करता है, दरअसल एक इतर परंपरा है. यह मुख्यधारा के धर्मों में कुलीन जाति के दबदबे की वजह से अलग-थलग पड़ गए दलितों को अपनी ओर खींचती है. डेरों ने भी अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए रंगारंग समागमों और म्यूजिकल नाइट्स का इस्तेमाल किया, पर एक के बाद एक विवादों ने उन पर ग्रहण लगा दिया. पटियाला में रहने वाले टिप्पणीकार जयबैंस सिंह कहते हैं, ''वह जगह तुरत-फुरत चंगा कर देने वाले ईसाइयों ने हथिया ली.''

मगर उससे पहले डेरा आंदोलन ने दलितों को ग्रामीण पंजाब में भू-अधिकारों के लिए आंदोलन चलाने और आम तौर पर जट सिखों के दमन के खिलाफ खड़े होने का आत्मविश्वास दिया. 20 फीसद से भी कम जाट राज्य की राजनीति में दबदबा रखते हैं—आजादी के बाद केवल दो मुख्यमंत्री, ज्ञानी जैल सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी, गैर-जाट थे. जाट 93 फीसद खेतिहर जमीन के भी मालिक हैं और इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं. उन्हें पुलिस, अफसरशाही और न्यायपालिका के शीर्ष पायदानों पर भी पाएंगे. सिख संस्थाओं में उनका फरमान ही अंतिम है. मगर धार्मिक मामलों में भी विद्रोही भावना ने जड़ें पकड़ ली हैं. 2010 में डेरा सचखंड ने विवादास्पद ऐलान किया कि रविदसिए अलग धर्म के हैं और उनके पूजास्थलों में गुरु ग्रंथ साहिब की जगह संत रविदास की अमृतबानी होनी चाहिए. मजहबियों, रामदसियों, जाटों और रामाग्रहिया सिखों सरीखे पिछड़ों के लिए अलग-अलग गुरुद्वारों के उभरने के साथ सिखी के भीतर जाति के आधार पर परस्पर दूरी वैसे भी साफ दिखाई देती है. अलग सामुदायिक विवाह स्थल

अरसे तक आतंकवाद, खेती का संकट और युवा पीढ़ी में नशाखोरी जैसी कई त्रासदियों का सामना करने वाला पंजाब उस ईसाइयत के लिए उर्वर जमीन साबित हुआ जिसे वे ''दुनिया के दबे-कुचलों का रहनुमा'' बताते हैं

और शवदाह गृह भी विरले नहीं हैं.

करिश्माई ईसाईयत के अक्षरधाम खंब्रा की ओर फिर लौटें. यहां की परमानंद की अनुभूति के धुंधलके में तमाम अहम सवाल हवा हो जाते हैं. कोई 5,000 समागमी भजनों पर झूम रहे हैं. आर्थिक दृष्टि में उनमें हर तबके के लोग हैं—उनमें से कुछ रविवार को डोसा खाने बाहर निकले मध्यवर्गीय पंजाबी परिवारों की तरह हो सकते हैं, जब तक कि आप उनके मिजाज को करीब से जाकर न भांपें. एक युवा दंपती अपने सामने करीबी रिश्तेदारों की तीन तस्वीरें बिछाए बैठा है. एक गर्भवती महिला संजीदगी से तल्लीन है. खड़े हुए लोग गुलाबी रंग के पवित्र जल से भरी प्लास्टिक की छोटी शीशियां माथे से लगाते हैं और आंख मूंदे-मूंदे दूसरा हाथ इस तरह आगे फैलाते हैं मानो उन पर यीशु अवतरित हो रहे हों. यहां तक कि तैनात स्वयंसेवकों पर भी यही मनोदशा तारी हो जाती है. यहां चार विशाल वीडियो स्क्रीन के सामने, जहां एक बहुत बड़ा सलीब मुख्य स्क्रीन पर एक लोगो की तरह घूम रहा है, आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं: द ग्रेट इंडियन होप ट्रिक या उम्मीद जगाने का भारतीय करतब. शाम को 'इंस्टैंट हीलिंग टेस्टिमनी संडे डिलिवरेंस' बैठक पेशेवर ढंग से आयोजित मंचीय शो है, जिसमें रणनीतिक तरीके से कैमरे लगाए गए हैं और ज्यों-ज्यों संगीत ऊंचा उठता जाता है, श्रद्धालु एक के बाद एक मंच पर आकर बताते हैं कि किस तरह नरूला के जादुई हाथ ने उन्हें चमत्कारिक ढंग से चंगा कर दिया. महाराष्ट्र की एक लड़की कहती है, ''अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मेरा लकवा भी ठीक हो जाएगा...''

बाहर धान के खेतों में घुमंतू गूजर आदिवासी अपनी भैंसों के लिए पराली (भूसे) के पूले उठाकर ले जा रहे हैं. मतलब, जितना भी वे उठाकर ले सकते हैं. बाकी जला दिए जाते हैं और पंजाब के ऊपर धुएं की चादर बनाने के काम आते हैं. ■

खतरे की जद में
दिल्ली के मोतीनगर में सड़क पार करती एक महिला को घेरे कुत्ते

हार्दिक छाबड़ा

जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई

देश भर में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ रहीं. इससे इस संवेदनशील मसले पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि इनसान और कुत्ते क्या एक साथ प्रेम से रह सकते हैं?

सोनाली आचार्जी और सुहानी सिंह

नोएडा की रहने वाली 49 वर्षीया उमा शर्मा के लिए घर के बाहर गली के छह कुत्तों को रोटी खिलाना, चार साल पहले पति की मौत के सदमे से उबरने का एक जरिया था. उन कुत्तों का प्यार और वफादारी का साथ न होता तो शायद वे डिप्रेशन का शिकार हो जातीं. लेकिन उनकी हाउसिंग सोसाइटी के दूसरे लोगों में कुत्तों के प्रति वैसा लगाव न था. साल भर पहले जब वे शहर से बाहर थीं, सोसाइटी के लोगों ने उनमें से चार कुत्तों को उठाया और कहीं और पहुंचा दिया. शर्मा कहती हैं, ''इससे मेरा दिल टूट गया. इससे उबरने को उन्हें इलाज कराना पड़ा. कुत्तों ने कभी किसी को काटा या दौड़ाया नहीं था. उन्हें टीके लगे थे. पर समाज के कुछ सदस्यों के पूर्वाग्रहों की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी.'' कुत्ते अपना एक इलाका बनाकर रखते हैं और नए इलाके में पहुंचा देने

पर अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती है. वहां पहले से मौजूद कुत्ते बाहरी की घुसपैठ को आसानी से नहीं स्वीकारते.

कुत्तों को रोटी खिलाना पशु प्रेमियों और उनके विरोधियों के बीच विवाद की पुरानी वजह रही है. पूरे भारत में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ने से यह विवाद और तेज हो गया है, जिससे लोगों में एक तरह की दहशत फैल गई है. अक्तूबर में ओडिशा के बोलांगिर जिले के पटनागढ़ ब्लॉक में तीन साल की एक बच्ची को कुत्तों ने मार डाला. सितंबर में केरल के कोझिकोड जिले में एक 12 वर्षीय लड़के पर आवारा कुत्ते ने उसके घर के सामने हमला किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अप्रैल में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने लखनऊ के मुसाहबगंज इलाके में सात और पांच साल के दो बच्चों पर हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई.

शर्मा ने सोसाइटी के सदस्यों के खिलाफ क्रूरता का मामला दर्ज कराया है. वे कहती हैं, ''कानूनन उन लोगों को बाकी दो कुत्तों को छूने की मनाही है.'' उन्होंने बताया कि कई बच्चों और सोसाइटी के गार्डों के लिए भी वे कुत्ते दोस्त सरीखे थे. शर्मा कहती हैं, ''जब तक वे किसी को नुक्सान नहीं पहुंचा रहे, हम उनसे छुटकारा पाने की सोचें ही क्यों?''

यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोग बॉम्बे हाइकोर्ट के हाल के एक फैसले की रोशनी में पूछ रहे हैं, जिसमें नागपुर में घरों के बाहर आवारा कुत्तों को रोटी खिलाने वालों पर जुर्माना लगाया गया है. फैसले के खिलाफ, 30 अक्तूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में कुत्तों को खिलाने वाले करीब 1,500 लोगों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया. उनका अहम ऐतराज यह है कि अदालत नागरिक निकायों को कुत्तों की आबादी के बेहतर नियंत्रण के लिए नसबंदी कार्यक्रमों में सुधार करने को कहने और ज्यादा सहिष्णु समाज बनाने के कदम उठाने की बजाए सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर डाल रही है जो उन्हें खिलाते हैं. पशु विशेषज्ञों का कहना है कि डॉग फीडर्स को दोष नहीं देना चाहिए. मुंबई के द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स के सीईओ अबोध अरास कहते हैं, ''पशु कल्याण संगठनों और पालिका अधिकारियों को नसबंदी के लिए कुत्तों को पकड़ने में मदद करके फीडर्स बड़ी सेवा कर रहे हैं. उन्हें दोष देने का कोई मतलब नहीं. अरास कहते हैं, ''कुत्तों को खाना खिलाना बंद कर दो' तो वे गायब हो जाएंगे? इसका उलटा हो सकता है. भूखे कुत्ते की तुलना में खाए-पिए कुत्ते के ज्यादा शांत रहने की संभावना है. मानव हितों और आवारा कुत्तों के कल्याण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है.''

10%

अखिल भारतीय स्तर पर आवारा कुत्तों की आबादी घटी है, 2012 से 2019 के बीच

50%

आबादी घटी है आवारा कुत्तों की, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में. किसी भी राज्य में यह सबसे ज्यादा गिरावट है

36%

दुनिया में रैबीज से होने वाली कुल मौतों में से 36 फीसदी भारत में होती हैं

स्रोतः द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स डेटा; लोकसभा के आंकड़े; डब्लूएचओ

आवारा कुत्तों को रोटी खिलाने के खिलाफ खड़े लोगों का कहना है कि ऐसे कुत्ते ने किसी व्यक्ति या पालतू कुत्ते पर हमला किया तो किसी को तो उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी. पुणे की एक गृहिणी और 35 वर्षीया सोनाली बत्रा कहती हैं, ''मैं पशु प्रेमी हूं पर मैं कुत्तों को बाहर नहीं खिलाती क्योंकि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती.'' उन्हीं की तरह अधिकांश फीडर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं. भोपाल की वकील वान्या झा आवारा कुत्तों को नियमित रोटी खिलाती हैं. वे कहती हैं, ''मैं कुत्ते के काटने पर इलाज में मदद करूंगी पर एक दायित्व के रूप में तब तक नहीं जब तक कि उस आवारा कुत्ते को मैंने अपना न लिया हो. और उस स्थिति में वह आवारा नहीं रहेगा. और वैसे भी आम तौर पर आवारा पशुओं को कोई एक आदमी या परिवार नहीं खिलाता.''

कानूनन, सभी को भूखे मर रहे जानवरों को खिलाने और देखभाल करने का अधिकार है. 2021 में दिल्ली हाइ कोर्ट ने कहा था कि ''... जानवरों को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है'' अदालत ने आगे कहा कि ''यह आरडब्ल्यूए या नगर निगम और पुलिस जैसे प्रवर्तन अधिकारियों सहित सभी सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वे समुदाय के जानवरों की देखभाल करने वालों को सभी सहायता प्रदान करें और पक्का करें कि कोई उन्हें बाधा न पहुंचाने पाए.'' सुप्रीम कोर्ट ने भी 19 मई, 2022 के अपने आदेश में उस फैसले को बरकरार रखा. 2014 में शीर्ष अदालत ने यह भी माना था कि सामुदायिक जानवरों को खिलाने पर कोई प्रतिबंध या उन्हें हटाना या उनके साथ किसी भी तरह की क्रूरता को सम्मान से जीने के उनके अधिकार का सीधा उल्लंघन माना जाएगा. फिर भी फीडर अक्सर खुद को और जिन कुत्तों की वे देखभाल करते हैं, उन्हें परेशानी में पाते हैं. अपने पीजी आवास के बाहर नौ कुत्तों को रोटी खिलाने वालीं, नोएडा में एमबीए की 28 वर्षीया छात्रा अदिति चतुर्वेदी कहती हैं, ''कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ पुरुषों ने मुझे सार्वजनिक रूप से गाली दी और धमकी दी गई कि कुत्तों ने किसी को भी काटा तो वे मुझे पीटेंगे. पर मैं ऐसे गुंडों से डरने वाली नहीं. ये वही लोग हैं जो दूसरों को फटकारेंगे कि आप समाज को नुक्सान पहुंचा रहे हैं लेकिन खुद पटाखे फोड़ेंगे और सड़कों पर जहरीला कचरा डालेंगे जो कहीं ज्यादा नुक्सानदेह है.''

दिल्ली स्थित एनजीओ फ्रेंडिकोज के कार्यकारी सदस्य कार्तिक सत्यनारायण सरीखे आवारा कुत्तों के साथ काम करने वालों का कहना है कि अगर जिम्मेदारी केवल फीडरों पर डालनी है फिर तो समाधान नहीं मिल सकता. वे कहते हैं, ''अगर हमें पड़ोसी नापसंद है तो क्या हम उसके पास लगातार जाते रहेंगे और तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक कि वह कहीं दूर नहीं चला जाता? हमें साथ रहने का हुनर सीखना होगा और इसके तरीके खोजने होंगे.'' सत्यनारायण आगे जोड़ते हैं, पहली बात तो वास्तव में विचार करने योग्य है. तथ्य यह है कि दुनिया में आवारा कुत्तों के नियंत्रण के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें से सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक भारत का भी है. ''नगरपालिकाएं और एनजीओ कुत्तों की नसबंदी करने का काम करते हैं, जिससे सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या पहले से कम हो गई है. इन कुत्तों को भी टीका लगाया जाता है और पहले वाली जगह पर ही पहुंचा दिया जाता है.'' दिल्ली नगर निगम का एक ऐप है, जिस पर आप कुत्ते की नसबंदी, उसकी सर्जरी और रिलीज की तारीख भी ट्रैक कर सकते हैं. अकेले दक्षिणी दिल्ली में सालाना 40,000 कुत्तों की नसबंदी हो रही है. सत्यनारायण कहते हैं, ''गलियों के सारे कुत्तों को मारने का लक्ष्य नहीं है. बस पक्का करना है कि उनकी आबादी बेतहाशा न बढ़े.''

मंदार देवधर

जनसंख्या विस्फोट का सच

2021 में पेट होमलेसनेस इंडेक्स के आंकड़ों में अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 6.2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं. यह 100 लोगों पर लगभग पांच कुत्तों का अनुपात है जो अभी भी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के मानक आंकड़े—100 लोगों पर तीन कुत्ते—से ऊपर है. हालांकि आंकड़े बताते हैं कि संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है. इस साल लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, 2012 से 2019 तक उनकी आबादी में अखिल भारतीय स्तर पर 10 फीसद की गिरावट दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश में तो इनकी आबादी 2012 में 42 लाख से घटकर 2019 में 21 लाख हो गई. सबसे ज्यादा वृद्धि कर्नाटक और उसके बाद राजस्थान में हुई. 2019 की कुत्तों की जनगणना में मणिपुर और दादरा, नगर हवेली दो ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें आवारा कुत्तों से मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था. सत्यनारायण कहते हैं, ''कुत्ते सड़कों पर औसतन लगभग छह साल ही रह पाते हैं क्योंकि यहां सबसे मजबूत और समर्थवान ही अस्तित्व बचा पाता है. एक साथ पैदा हुए झुंड में से केवल एक या दो ही पिल्ले जीवित रहते हैं. तो यह एक गलत धारणा है कि हम आवारा कुत्तों के मामले में एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का सामना कर रहे हैं.''

आवारा कुत्तों के इलाके में अगर फंस जाएं तो आखिर करें क्या

उन पर न तो कुछ फेंकें, न उन्हें दौड़ाएं या न जोर की आवाज के साथ और न ही हाथ ऊपर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश करें. इससे वे चौंक और घबरा करके आक्रामक हो सकते हैं. अपने बच्चों को भी यह बात अच्छी तरह से समझाएं कि आवारा कुत्तों के साथ दूरी बनाकर चलें

जब तक उकसाएं न, कुत्ते हमला नहीं करते
फिर भी अगर आप गुर्राते कुत्ते के सामने पड़ जाएं तो भागें नहीं. तनकर खड़े रहें, उसे महसूस कराएं कि आप डर नहीं रहे और फिर धीरे-धीरे वहां से हटें. जरूरत पड़े तो किसी को मदद के लिए बुलाएं. ज्यादा लोगों के दिखने पर कुत्ते अमूमन खिसक लेते हैं

विशेषज्ञों की राय में, यह महत्वपूर्ण है कि जिन राज्यों में नसबंदी कार्यक्रम पर्याप्त नतीजे नहीं दे रहे हैं, वे बेहतर जनसंख्या नियंत्रण के लिए दूसरे प्रयास तेज करें. इसी लोकसभा रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और केरल में संख्या में 1,00,000 से भी कम की वृद्धि हुई है. अरास कहते हैं, ''जहां भी पशु जन्म नियंत्रण नियम लागू किए गए हैं, वहां आपको आवारा कुत्तों के मनुष्यों पर हमला करने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी. एक सुसंगत नसबंदी कार्यक्रम होना चाहिए जो पूरे समूह के मूल व्यवहार को बदल दे. ''पशु कल्याण पर केंद्र सरकार की सर्वोच्च संस्था, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने सभी राज्यों को एक सक्रिय नसबंदी कार्यक्रम बनाकर नियमों का पालन करने के लिए कहा है. पेटा इंडिया की पशुओं के साथ क्रूरता पर प्रतिक्रिया देने वाली परियोजनाओं के प्रबंधक मीत अशर कहते हैं, ''अगर कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाती है, तो उनके बीच झगड़े हो सकते हैं, और कभी-कभार शायद कोई इनसान उस लड़ाई में फंस जाता है. प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम ऐसी स्थितियों को रोकने में मदद करता है. बेहतर नसबंदी कार्यक्रम न होने से इलाके में नए कुत्तों के लिए जगह नहीं बन पाती. कुत्तों की प्राकृतिक मौत के जरिए उनकी संख्या घटती है.'' नसबंदी किसी झुंड में एक कुत्ते के वर्चस्व वाली मानसिकता को खत्म करने में मदद करती है क्योंकि वे हॉर्मोन जो कुत्ते को मादा या फिर इलाके पर कब्जे के लिए प्रतिस्पर्धा करने को प्रेरित करते हैं, वे अब मौजूद नहीं होते. अशर कहते हैं, ''नसबंदी, टीकाकरण, अच्छा भोजन और देखभाल पाने वाले सामुदायिक कुत्ते भी बिना नसबंदी, बिना टीका वाले और अजनबी कुत्तों को अपने क्षेत्र में घुसने से रोकते हैं. यह प्रक्रिया आस-पड़ोस में सामुदायिक कुत्तों की आबादी को स्थिर करती है.''

लेकिन गली के कुत्तों की नसबंदी करना हमेशा आसान काम नहीं होता. कई नगरपालिकाओं के लिए उन्हें पकड़ना एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि कुत्ते भाग जाते हैं या अजनबियों पर हमला करते हैं. भोपाल नगरपालिका सीमा में कुत्तों की नसबंदी करने वाली एजेंसी नवोदय के पशु चिकित्सक डॉ. उमेश भास्कर कहते हैं, ''कभी-कभी कुत्ता प्रेमी जानवरों को नसबंदी के लिए ले जाने का विरोध करते हैं. वे जानना चाहते हैं कि कुत्तों को कहां ले जाया जा रहा है और वे कब वापस आएंगे. लोगों को यह बताने के लिए अधिक जागरूकता की जरूरत है कि आवारा कुत्तों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी नसबंदी सबसे अच्छा उपाय है.'' पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम, 2001 में कहा गया है कि नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें लाया गया था. लेकिन जब कुत्तों को वापस करने का समय आया, कुछ नगरपालिकाओं को खतरों का सामना करना पड़ा. नाम न छापने की शर्त पर दिल्ली नगरपालिका के एक सदस्य बताते हैं, ''हमें कुत्तों को इकट्ठा करने के लिए और कभी-कभी हमें उन्हें रिहा करने के लिए लड़ना पड़ता है क्योंकि हर कोई उन्हें वापस नहीं चाहता. देश गली के कुत्तों को लेकर बंटा हुआ है और प्रेम-नफरत का यह विभाजन अक्सर हमारे काम के रास्ते में आ जाता है.''

कुछ शहरों में नागरिक निकायों ने महसूस किया है कि फीडरों के साथ काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं. मुंबई एक ऐसी

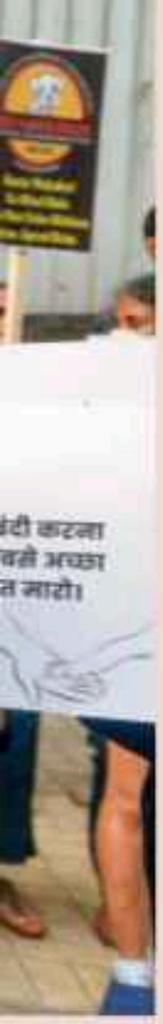

←

हमदर्दी
नागपुर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को दंडित करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मौन प्रदर्शन करते लोग

पुचकारे जाने के लिए नजदीक आने पर कुत्ते के किसी अंग को न छेड़ें खासकर पूंछ को

दुम हिलाते हुए पास आते किसी कुत्ते के साथ आप अगर सहज महसूस नहीं करते तो उसे डराने या धमकाने की बजाए बस धीरे-धीरे चलते जाएं. कुत्ते अपने इलाके के बाहर पीछा नहीं करेंगे

इसके बाद भी अगर आपको डर लगता है तो कुत्तों के इलाके से गुजरने के लिए सोसाइटी के गार्डों या कुत्तों को रोटी खिलाने वालों से मदद मांगें. इलाके में कुत्ते किसी के हिले-मिले होते ही हैं

मिसाल है जहां फीडर कुत्तों को पकड़ने में मदद करते हैं और यह पक्का करते हैं कि उनकी देखरेख में सभी कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी का काम पूरा हो. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बदले में, 2022-2023 में अपने नसबंदी बजट के लिए 4 करोड़ रुपए अलग रखे हैं और फीडरों का कहना है कि प्रक्रिया हमेशा सुचारु रूप से पूरी होती रही है. बीएमसी में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के महाप्रबंधक डॉ. कलीमपाशा पठान कहते हैं, ''हर कोई आवारा कुत्तों को उपद्रव के रूप में देखता है और चाहता है कि उन्हें उनके परिसर से दूर ले जाया जाए. सह-अस्तित्व बेहद अहम है; कुत्ते हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं. आवारा कुत्तों की आबादी को एक ऐसे आंकड़े तक ले जाने की जरूरत है, जिसे क्षेत्र की मानव आबादी अच्छी तरह से स्वीकार ले, ताकि किसी भी संघर्ष को टाला जा सके. आवारा कुत्ते अगर स्वस्थ और साफ-सुथरे रहते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं तो संघर्ष और समस्याएं कम हो जाती हैं.'' सितंबर तक नगर निकाय ने 3,86,347 कुत्तों की नसबंदी की है और एक वार्षिक रेबीज टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें एक वर्ष में 1,00,000 टीकाकरण की उम्मीद है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाभर में रेबीज से हर साल लगभग 20,000 मौतें होती हैं जिनमें से 36 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं. और भारत में रेबीज के लगभग सभी मामले कुत्तों के काटने से ही सामने आते हैं. देश 2030 तक रेबीज के मामले पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और नसबंदी के लिए लाए गए सभी आवारा कुत्तों को इसका टीका अनिवार्य रूप से दिया जाता है.

आवारा कुत्तों के साथ जीना

इस साल लोकसभा में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री के पेश किए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत भर में आवारा कुत्तों के काटने की संख्या 2019 में 73 लाख से घटकर 2021 में 17 लाख हो गई है. और यह नसबंदी कराए गए कुत्तों के भी काटने की घटनाओं से इनकार नहीं करता. यानी यह मानना गलत है कि जिन कुत्तों की नसबंदी हो गई है, वे काटेंगे ही नहीं.

विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्ता किसी खतरे को भांपने पर अपनी रक्षा में काटता या हमला करता है. और नसबंदी कराया गया कुत्ता बिना उकसावे के हमला नहीं करेगा, लेकिन खतरे की स्थिति में बचाव में हमला करेगा. जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960, ऐसे कृत्यों को परिभाषित करता है जो जानवरों के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आते हैं और उन्हें दंडनीय बनाते हैं. इन कृत्यों में ''किसी भी जानवर को पीटना, लात मारना, हमला करना या प्रताड़ित करना ताकि उन्हें अनावश्यक दर्द या पीड़ा हो'' शामिल हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, आवारा कुत्तों को नुक्सान पहुंचाने पर आमादा लोगों की संख्या कम करने के तरीकों में से एक यह है कि हम देखें कि कुत्ते हमारे लिए कितने उपयोगी हैं. कई लोगों के लिए मूल्यवान सहयोगी होने के अलावा, कुत्ते रात में रिक्त स्थानों को सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं. वे एक जैविक सफाईकर्ता हैं जो हमें कचरे, चूहों और दूसरे जानवरों से बचाते हैं.

दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन क्षेत्र में 45 कुत्तों की देखभाल करने वाले सुनील कुट्टम सह-अस्तित्व की अच्छी मिसाल हैं. सभी कुत्तों का टीकाकरण किया जाता है और संबंधित आरडब्ल्यूए के पास उनके प्रमाण पत्र होते हैं. कुट्टम और उनकी टीम नई नौकरानियों, ड्राइवरों और कूरियर वालों की कुत्तों से पहचान कराने में मदद करती है.

चंद्रदीप कुमार

देखभाल
सुनील कुट्टम आवारा कुत्तों के साथ

आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं उतनी भी ज्यादा नहीं हैं जितनी कि धारणा बन गई है. और न ही आवारा कुत्ते ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं

यह जानना भी जरूरी है कि आवारा कुत्तों के काटने की संख्या उतनी नहीं जितनी की मानी जा रही है और न ही आवारा कुत्ते ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं. एर्णाकुलम, केरल के सरकारी अस्पताल के अनुसार, 2015 में छह महीने की अवधि में कुत्ते काटने के 75.6 प्रतिशत मामले पालतू कुत्तों के आए थे न कि आवारा कुत्तों के. विकसित देशों में ऐसे कुत्तों की आबादी को नसबंदी कार्यक्रमों से बल्कि उन्हें आश्रय देकर भी नियंत्रित किया जाता है. नोएडा प्राधिकरण अमेरिका से कुछ सीख ले रहा है. नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने इंडिया टुडे से कहा, ''आरडब्ल्यूए की मदद से शहर में कुत्तों के लिए 18 आश्रय गृह बनाने की योजना बन रही है. ये आश्रय गृह आरडब्ल्यूए ही चलाएंगे और आवारा कुत्तों को रहने और बीमार होने पर इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे. हम भी इसमें मदद करेंगे. सेक्टर 135 में डॉग पार्क भी बनाया जा रहा है.'' कुत्तों की अहमियत और उनके साथ उचित व्यवहार को लेकर जागरूकता, उनकी आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी और तय स्थानों पर उन्हें खिलाना, ऐसे उपाय इनसान और कुत्तों के बीच स्वस्थ सह-अस्तित्व की बुनियाद बन सकते हैं.

—साथ में **मनीष दीक्षित, राहुल नरोन्हा** और **रोहित परिहार**

चंद्रदीप कुमार

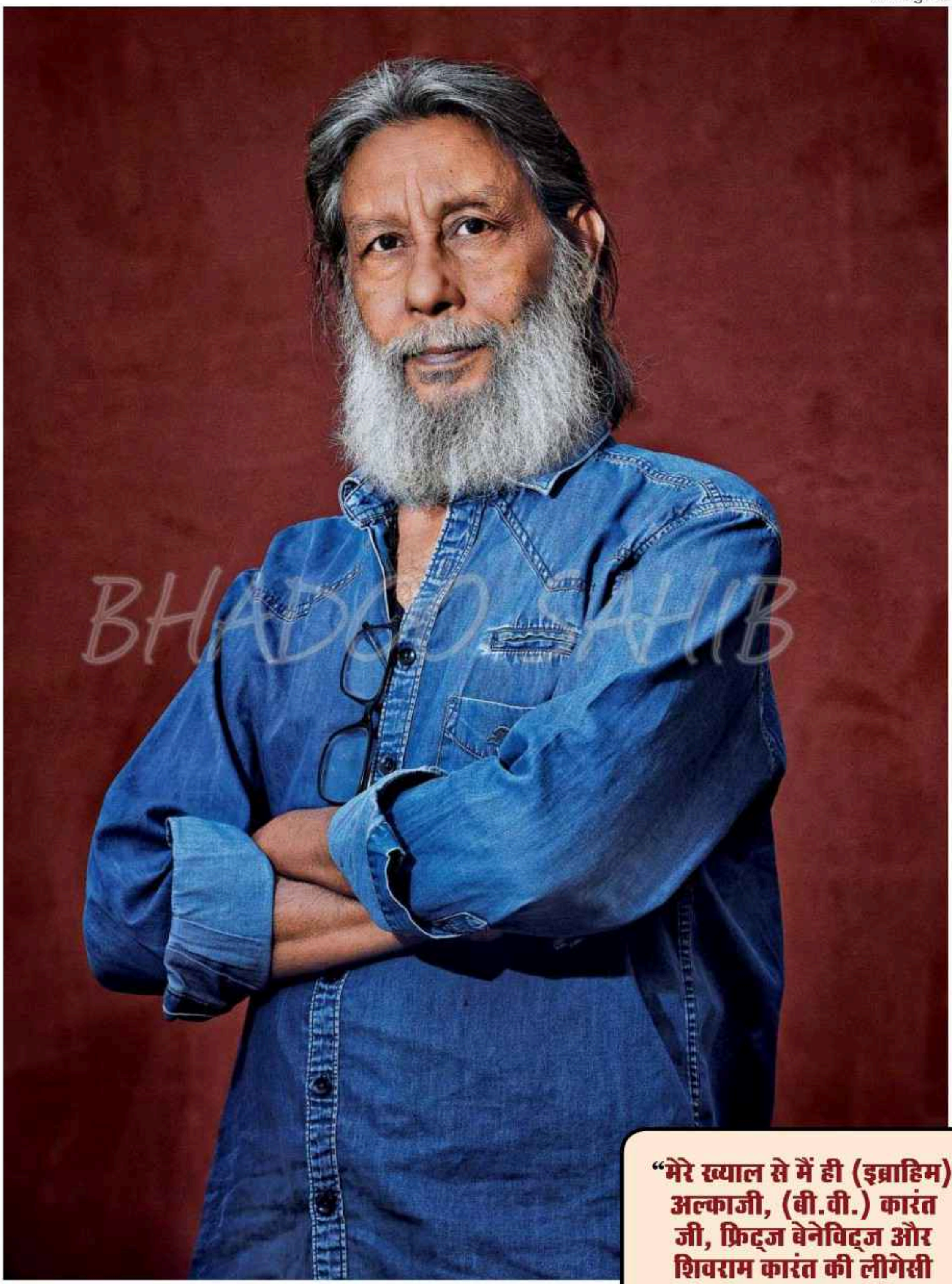

"मेरे ख्याल से मैं ही (इब्राहिम) अल्काजी, (बी.वी.) कारंत जी, फ्रिट्ज बेनेविट्ज और शिवराम कारंत की लीगेसी को कैरी कर रहा था. मैंने खुद को मिटा रखा था"

जब बोलता है गुरु ज्ञानी

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में करीब चार दशक तक पढ़ाने वाले एक प्रयोगधर्मी प्रशिक्षक ने तैयार की दिग्गज अभिनेताओं, रंगकर्मियों की बड़ी जमात. अपने दिलचस्प सफर, काम, टेक्नीक और भविष्य की योजनाओं पर बतियाते रॉबिन दास

शिवकेश

यह बात है 1976 की. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में पढ़ रहे रॉबिन कुमार दास से थर्ड ईयर में क्लासमेट और अब मशहूर अभिनेता पंकज कपूर ने उनके भविष्य को लेकर सवाल किया था: ''तू डिजाइन भी कर रहा है, डायरेक्शन भी करता है, ऐक्टिंग भी करना चाह रहा है. आखिर क्या करेगा तू?'' उन्होंने मजाक में ही जवाब दिया था: ''मेरी गर्लफ्रेंड जहां होगी, उसके साथ जो भी करने का मौका मिलेगा, मैं वही करूंगा.'' और किस्सा-ए-मुख्तसर यह कि ओडिशा के बालेश्वर जिले का यह नौजवान अगले ही साल एनएसडी में सीनिक डिजाइन का एसोसिएट प्रोफेसर बन गया. 37 साल बाद 2014 में जब वे रिटायर हुए तो न सिर्फ एनएसडी में सबसे लंबे समय तक पढ़ाने का रिकॉर्ड बनाया बल्कि यहां से निकले 1,100 में से 500 से ज्यादा कलाकारों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के काबिल बनाने में उनका निर्णायक रोल रहा. 'रॉबिन दा'. आप बस इतना बोल दें, देश-दुनिया में मौजूद उनका कोई भी छात्र आगे उनसे जुड़ा दिलचस्प किस्सा, पूरे अदब और एहतराम के साथ जोड़ देगा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और स्वानंद किरकिरे की बैचमेट रहीं, गुल्लक सीरीज की शांति गीतांजलि कुलकर्णी की सुनिए, ''शुरू में वे पेड़-पौधों, प्राणियों के बारे में पढ़ा रहे थे. 20 साल की थी. उतना समझी नहीं. पर जब वे बाकी इतिहास नाटक कराने लगे, तब उसके अर्थ खुले.'' हाल में एनएसडी के सेकंड ईयर के छात्रों को दो हिस्सों में बांटकर दास और बापी बोस (1986 बैच) के निर्देशन में शेक्सपियर का नाटक वेनिस का सौदागर कराया गया. दोनों की प्रस्तुतियों में तुलना लाजिमी थी. पर बोस सिर झुकाते हुए कहते हैं: ''उनसे तुलना! सवाल ही नहीं. मेरे गुरु रहे हैं वे. उस आदमी का अनआर्थोडॉक्स अप्रोच आपको चैलेंज करता है, चौंकाता है. उनसे पढ़कर आप वही नहीं रह सकते जो पहले थे.'' रॉबिन दा ने अब दूसरी पारी के तौर पर सिनेमा और सीरीज में अभिनय शुरू किया है. एक किरदार के वास्ते ही उन्होंने बाल बढ़ा रखे हैं. नई बनती फिल्म सिटी के पास नोएडा के कलाधाम में वे ऐक्टिंग ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रहे हैं. अपने लंबे सफर, एनएसडी और नई पहल के बारे में रॉबन दा से बातचीत के अंश:

"रॉबिन सर हमारे सच, हमारी कमजोरियों और ऑब्जर्वेशन के बारे में जो बताते थे, वह समझ आज मुझे अपने किरदारों को तैयार करने में बहुत मदद करती है"

–गीतांजलि कुलकर्णी
अभिनेत्री

● थिएटर की दुनिया वाले और स्टुडेंट्स सभी आपको रॉबिन दा कहकर बुलाते हैं. यह आपके प्रति उनका...

दरअसल (टीचिंग के दिनों में) मैं शादीशुदा होने के बावजूद छड़ों की तरह स्टुडेंट्स के बीच घुल-मिल जाता था, रात-दिन काम करता था. उनके साथ एक तरह का दोस्ताना होने की वजह से वे सर नहीं, रॉबिन दा कहते थे. सन् 2000 से ऑनवर्ड्स जितने मेरे पढ़ाए हुए हैं, या शायद कुछ ऐसे लोग जो खुद बड़े हो जाते हैं तो फिर मुझे सर से दा तक ले आते हैं (हंसते हुए), जो अब मुझे पसंद नहीं. जवान था तब ठीक था. ये बंगाली टच मुझे ठीक नहीं लगता. मैं ओडिशा का हूं, हम लोग दादा तो अपने चाचा को ही बोलते हैं. और ये दा शब्द आल्मोस्ट डेरोगेटरी (लगभग अपमानजनक) हो गया है. नई जेनरेशन वाला कोई बोलता है तो मैं डपट देता हूं. जिस कदर जी-जान लगाकर मैंने काम किया है, एनएसडी में मेरा जिस तरह का योगदान है, इस इंस्टीट्यूशन का जो स्टैंडर्ड है, और जो मेरी सीनियॉरिटी है, यह टाइटल शायद उस सबको खंडित कर देता है. इतना फैमिलियर! मेरे ख्याल से मैं ही (इब्राहिम) अल्काजी, (बी.वी.) कारंत जी, बैरी जॉन, फ्रिट्ज बेनेविट्ज और शिवराम कारंत की लीगेसी को कैरी कर रहा था. खुद को मिटा रखा था. मैं शायद इन लोगों के काम का ट्रांसलेटर ही हूं... तो इस दा के पीछे बहुत प्यार है लेकिन हाल के वर्षों में यह खासा अपमानजनक हो गया है.

"अस्सी के दशक में नामी रंगकर्मियों को ही छात्रों के साथ नाटक करने बुलाया जाता था. अब तो एनएसडी का कोई भी टीचर डायरेक्ट कर रहा है और कुछ भी थ्योरी बकता है"

"मैं ओडिशा का हूं. हम लोग दादा तो अपने चाचा को बोलते हैं. और ये (रॉबिन) दा शब्द लगभग अपमानजनक है. नया कोई बोलता है तो डपट देता हूं"

दो फलक दास के: एनएसडी सेकंड ईयर के छात्रों की प्रस्तुति शेक्सपियर के *वेनिस का सौदागर* का एक दृश्य; (नीचे) दास के ही निर्देशन में ओडिया उपन्यासकार फकीर मोहन सेनापति की रचना पर पुरानी प्रस्तुति *छह बीघा जमीन*

दोनों फोटोः साभार एनएसडी

● आपने 37 साल एनएसडी में पढ़ाया. इरफान, आदिल हुसैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वानंद किरकिरे, राजपाल यादव और इसी तरह से थिएटर में सक्रिय बीसियों उम्दा कलाकार आपकी ट्रेनिंग लैब से निकले. एनएसडी के दिनों का आपका अनुभव कैसा रहा?

ऐक्टर बनने की चाहत के अलावा हाइस्कूल से ही मुझे ड्राइंग, स्केचिंग की आदत थी. टीचर बनने पर लगा कि डिजाइन, ऐक्टिंग और डायरेक्शन तीनों का मौका मिलेगा. ड्रामा स्कूल पास करने के बाद एक लफंडर स्टाइल मार के घूमता था मैं, फिर तय किया कि मैं यहीं रहूंगा. दूसरे टीचर पढ़ाने के बाद बाहर पैसे कमा रहे थे. मेरे अंदर कुछ आदर्शवादी पागलपन था. मुझे एक थिएटर लैब चाहिए था अपने प्रयोगों के लिए, तो अपना ग्रुप बनाया. सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइन पर मेरा ज्यादा जोर था. अस्सी का दौर था, एक तरफ बादल सरकार थर्ड थिएटर का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे, एक तरफ अल्काजी और एक तरफ कारंत जी. इन तीनों से छनकर कुछ चौथा ही रिजल्ट आ रहा था और ऑडियंस तुरंत बाउंसबैक भी कर रही थी. पर स्टेजवर्कर्स को बुरा लग रहा था कि स्टेजक्राफ्ट जैसे थर्ड डिग्री स्पेशलाइजेशन से निकला आदमी प्ले डायरेक्ट करेगा! उन्हें पता ही नहीं था कि मैं अंग्रेजी और ओडिया लिट्रेचर में ग्रेजुएशन करके आया था. 1985 तक आते-आते मेरे अंदर एक फॉर्मेट आ गया था कि इंडियन थिएटर का प्रस्तुतीकरण का तरीका यथार्थ की नकल करने का नहीं है. उसकी गहरी खोज भी करता रहा. ग्रोटोवस्की और ब्रेख्त को खूब पढ़ा. उस वक्त राष्ट्रीय परिदृश्य पर उच्च स्तर के नाटक प्रस्तुत कर चुके लोगों को ही स्टुडेंट्स के साथ नाटक डायरेक्ट करने के लिए बुलाया जाता था. आज तो ड्रामा स्कूल का कोई भी टीचर उठके प्ले डायरेक्ट करने लगता है और कुछ भी थ्यौरी वे लोग अपने आप में बकते हैं.

● एनएसडी के छात्रों में आपकी ट्रेनिंग स्टाइल के बड़े चर्चे रहे हैं. ओडिशा में एक बार आपने स्टुडेंट्स को पाला गायकों के आयोजन में परफॉर्म करने को कहा तो वे आधे घंटे में ही थक-चुक गए.

स्टुडेंट्स टुअर को मैंने नाम दे रखा था वर्कशॉप ऑन द व्हील्स. 2003 में एक बार ओडिशा ले गया. बस में मैं वहां के लैंडस्केप, क्लाइमेट और मंदिरों के वास्तुशिल्प को समझाते हुए चल रहा था. पर एक छात्र ईयरफोन लगाके कुछ सुन रहा था. मैं उसका ईयरफोन निकालकर बस से बाहर फेंका. बस रुकी. मैंने कहा, जब तक तुम लोगों को इसके फेंके जाने की वजह समझ में नहीं आती, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. यह क्लास पीरियड है. उन्हें समझ आ गया. इसी तरह से ब्लाइंड गेम करवाता था. आंख बंद करके एक ग्लोब, एक पिरामिड, ट्रैपेजियम और स्क्वायर को फील करो. फिर देखा कि कुछ लोग एक-दूसरे को चुटकी काट रहे हैं. मैंने तीन मिनट का मौन रखवाया और फिर कहा कि तुम सभी 21 लोग सामने वाले पेड़ को पांच मिनट अच्छी तरह से देखो. उसके बाद आंखें बंद करके चढ़ो. किसी को छूना नहीं, गिरना नहीं. मैं बताता जाता था कि कौन किससे कितनी दूरी पर है. मैंने कहा, अब आसपास जो भी है, उसे स्पर्श से अच्छी तरह महसूस करो. फिर सीटी बजाकर पांच मिनट में धीरे-धीरे उतरने को कहा. घंटे भर के इस अभ्यास में वे ऐसे ट्यून हुए कि बिना आंख खोले और बिना गिरे-पड़े एक जगह आ खड़े हुए. आर्ट एक्सरसाइज की यही खूबी है. जब छात्र का उससे लिंक बन जाता है फिर टीचर की कोई जरूरत नहीं बचती.

● जैसे साहित्य में किस्सागोई के दौरान कहते हैं, एक समय की बात है. सिनेमा-थिएटर में वह एक जगह की भी बात हो जाता है. पर आपने ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन की थ्यौरी के जरिए थोड़ा और आगे बढ़ाकर एक दरवाजे, खिड़की, कबर्ड जैसे खास एलिमेंट्स तक की बात बना दिया. इस प्रयोग के बारे में थोड़ा बताएं.

इन चीजों को ऐक्टर से कनेक्ट कराने का मतलब होता है कि वे ऐक्शन-रिएक्शन को ठीक से कर सकें. इमेजिनरी सिचुएशन में जाने पर स्पर्श की अनुभूति उजागर हो. मैं अभी यहीं अगर गांव की बात सोचने लगूं तो चारपाई पर बैठने पर पुट्ठों को होने वाली छुअन भी महसूस हो. अभी मेरे बड़े भाई के देहांत पर साल की लकड़ी और इनसानी मांस की जो गंध है वह मेरी ट्रैजिक मेमोरी का एक हिस्सा बन गई. इसी तरह से मौके की वस्तुओं/ प्रॉप्स से ऐक्टर के एहसास को जोड़ा जाता है और वे भाव उनके भीतर खुल पड़ेंगे.

● अब तो आप नए सिरे से सिनेमा में सक्रिय हो गए हैं.

मैं उस बारे में सीरियस नहीं हूं. बॉम्बे में नहीं, यहीं रहता हूं. 2018-19 में ऐक्टिंग से 20-25 लाख रु. कमा लिए थे. लॉकडाउन में मेरा मार्केट डाउन हो गया था पर अब फिर जोर पकड़ रहा है (हंसते हैं). *महारानी-2* में एकल मुंडा का अच्छा रोल मिल गया था. अभी नटवरलाल जैसा एक रोल मिला है. उसने बहादुरशाह जफर का गोल्डेन टॉयलेट चोरी करके अपने घर में लगा रखा है और एक शेर में ऐसा कुछ कहता है कि अब तो तशरीफ भी सुनहरी होगी. एक बनने जा रही *जनता बैंड* वेबसीरीज में मेरा मेजर रोल है.

● ऐक्टिंग ट्रेनिंग सेंटर की भी बात थी.

हां, नोएडा के कलाधाम में अपना एक स्टुडियो बन रहा था पर लॉकडाउन में कमाई खत्म होने से धीमा पड़ गया है, अभी सालेक लगेगा. एक डिजाइन ट्रेनिंग और ऐक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहूंगा. वहां परफॉर्मेंस तो नहीं पर रिहर्सल हो सकती है. मैं मिनिएचर ड्रामा नहीं कर सकता. ड्रामा स्कूल में मैंने अपने ऊपर ग्रैंड प्रोडक्शन का भार ले लिया था. अल्काजी, बैरी और कारंत के बाद मैं ही हूं जो इस भारी बोझ को उठा सकता हूं. कमर टूट जाती है मेरी.■

"महामारी से पहले एक फिल्म माफिया था"

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक कमल हासन के बाद सही मायनों में अदाकारी का जलवा प्रकाश राज ने ही बिखेरा है. उनसे ज़ी5 पर आ रही वेब सीरीज *मुखबिर* और दूसरे मुद्दों पर बातचीत

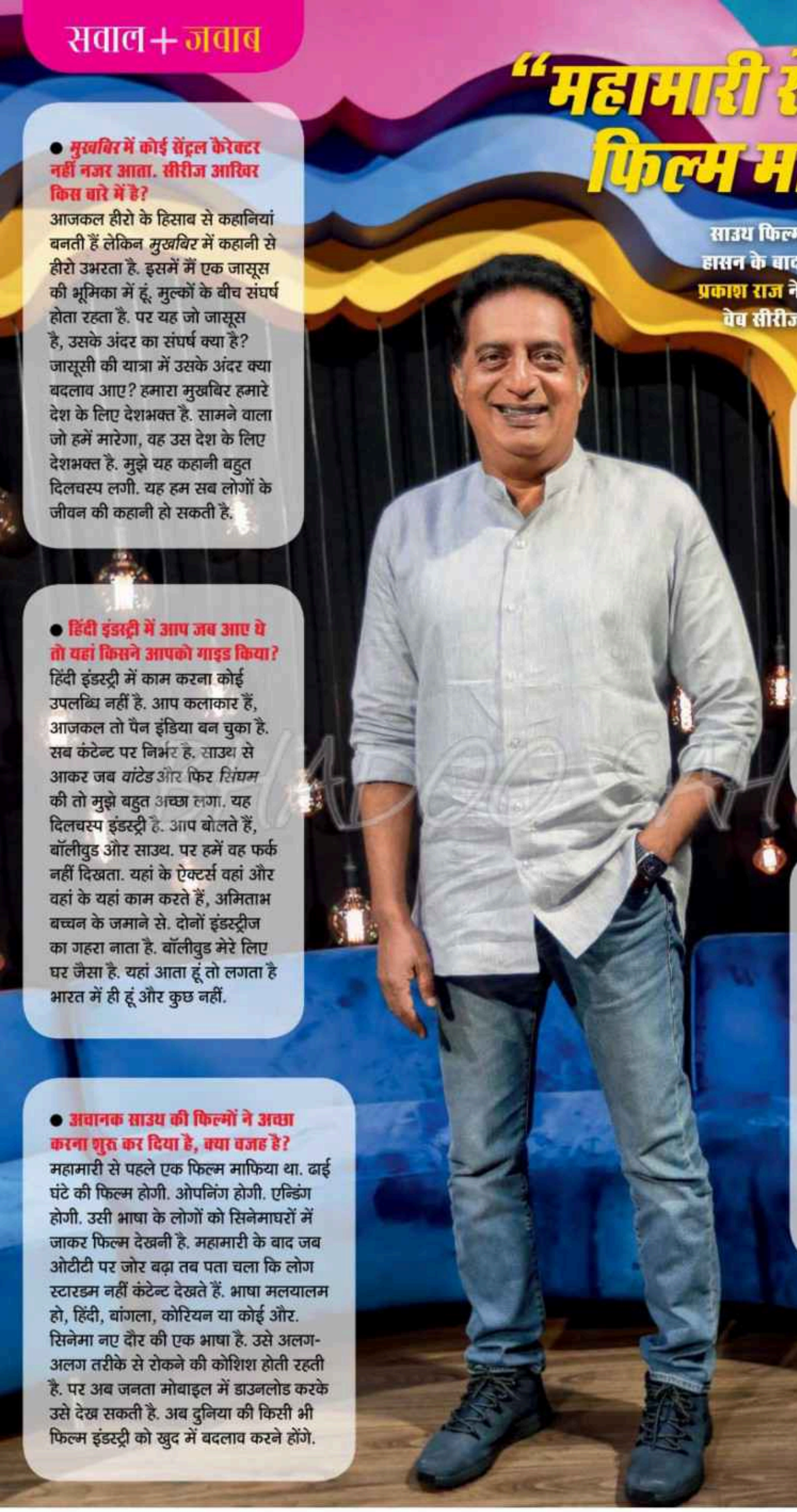

● *मुखबिर* में कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं नजर आता. सीरीज आखिर किस बारे में है?

आजकल हीरो के हिसाब से कहानियां बनती हैं लेकिन *मुखबिर* में कहानी से हीरो उभरता है. इसमें मैं एक जासूस की भूमिका में हूं. मुल्कों के बीच संघर्ष होता रहता है. पर यह जो जासूस है, उसके अंदर का संघर्ष क्या है? जासूसी की यात्रा में उसके अंदर क्या बदलाव आए? हमारा मुखबिर हमारे देश के लिए देशभक्त है. सामने वाला जो हमें मारेगा, वह उस देश के लिए देशभक्त है. मुझे यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी. यह हम सब लोगों के जीवन की कहानी हो सकती है.

● हिंदी इंडस्ट्री में आप जब आए थे तो वहां किसने आपको गाइड किया?

हिंदी इंडस्ट्री में काम करना कोई उपलब्धि नहीं है. आप कलाकार हैं, आजकल तो पैन इंडिया बन चुका है. सब कंटेन्ट पर निर्भर है. साउथ से आकर जब *वांटेड* और फिर *सिंघम* की तो मुझे बहुत अच्छा लगा. यह दिलचस्प इंडस्ट्री है. आप बोलते हैं, बॉलीवुड और साउथ. पर हमें वह फर्क नहीं दिखता. यहां के ऐक्टर्स वहां और वहां के यहां काम करते हैं, अमिताभ बच्चन के जमाने से. दोनों इंडस्ट्रीज का गहरा नाता है. बॉलीवुड मेरे लिए घर जैसा है. यहां आता हूं तो लगता है भारत में ही हूं और कुछ नहीं.

● अचानक साउथ की फिल्मों ने अच्छा करना शुरू कर दिया है, क्या वजह है?

महामारी से पहले एक फिल्म माफिया था. ढाई घंटे की फिल्म होगी. ओपनिंग होगी. एन्डिंग होगी. उसी भाषा के लोगों को सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखनी है. महामारी के बाद जब ओटीटी पर जोर बढ़ा तब पता चला कि लोग स्टारडम नहीं कंटेन्ट देखते हैं. भाषा मलयालम हो, हिंदी, बांगला, कोरियन या कोई और. सिनेमा नए दौर की एक भाषा है. उसे अलग-अलग तरीके से रोकने की कोशिश होती रहती है. पर अब जनता मोबाइल में डाउनलोड करके उसे देख सकती है. अब दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को खुद में बदलाव करने होंगे.

● आपकी ऐक्टिंग स्टाइल क्या है?

यह डिपेंड करता है कि फिल्म का जॉनर क्या है? लेंसिंग क्या है? शॉट्स कैसे हैं? एडिटिंग कैसी है? किस तरह के दर्शक को हम टारगेट कर रहे हैं? *सिंघम* जैसी कमर्शियल फिल्म में लाउड ऐक्टिंग करनी पड़ती है. जब *कांचीवरम* जैसी या मणिरत्नम की कोई फिल्म करता हूं तो टोन नीचे आ जाएगी. डायरेक्टर के कहे अनुसार करना है पर ध्यान रखना है कि फिल्म में कोई सियासी एजेंडा तो नहीं. कुछ भी करके यह सफाई देना कि जो दर्शक देख रहे हैं हम कर रहे हैं, ठीक नहीं. हम एक युग को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. हम एक कल्चर के एंबेसडर हैं.

● आपने सलमान खान के साथ भी काम किया. कैसा तजुर्बा रहा?

सलमान भाई बहुत प्यारे इनसान हैं. मैं उन्हें ऐक्टर के तौर पर नहीं देखता. वे एक शैतान बच्चे हैं. सलमान भाई कभी बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि वे कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं. वे चीजों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते. गुस्सा है तो गुस्सा. प्यार है तो प्यार. उनमें फिल्टर नहीं है. मुझे उनका साथ पसंद है. वे किसी से डरते नहीं. हां, वे शूटिंग पर देर से आते हैं. पर उनको पता है कि उनका मार्केट खासा बड़ा है. दस करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो होने दो. आराम से काम करो.

–अनुभव बाजपेयी

फोटो: मोहन कनौजिया